● वर्ष-3
● अंक-292
रायपुर, बुधवार
17 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› बरसात के मौसम में घर के फर्नीचर

पुंछ के जंगलों से निकला आतंकी जिन्न, अब तक 32 जवान शहीद

जम्मू। एक और आतंकी हमले में चार जवान बलिदान हो गए। पिछले तीन वर्ष में जम्मू संभाग में यह सातवां बड़ा हमला था। इन सात हमलों में अब तक 32 जवान बलिदान हो चुके हैं। पुंछ के भाटादूड़ियां के जंगलों से निकला आतंक का जिन्न डोडा पहुंच गया है। वहीं, आतंकियों पर कार्रवाई रणनीतिक बैठकों और सर्च ऑपरेशन से आगे नहीं बढ़ पा रही है।

पूर्व डीजीपी एसपी वैद का कहना है कि आतंकियों पर अब बड़ी और तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। जंगलों में छिपे आतंकियों पर कार्रवाई के लिए आधुनिक संचार नेटवर्क, खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। पूर्व मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जमवाल कहते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां अपने साथ जंगल के हर एक गांव को जोड़ें।

खासकर युवाओं और पूर्व सैनिकों को साथ जोड़ें। जम्मू संभाग में तैनात रह चुके स्थानीय पूर्व सैनिकों की मदद लेनी चाहिए। सुरक्षाबलों की संख्या बढ़ाने से जरूरी है कि आम लोगों को साथ जोड़ा जाए।

चमरेल से शुरू हुआ था सिलसिला

वर्ष 2021 में 11 अक्तूबर को पुंछ के डेरा गली चमरेल जंगल में आतंकियों की तलाश में निकली सेना पर घात लगाकर हमला हुआ था। इसमें पांच जवान बलिदान हो गए थे। इसके दो दिन बाद 14 अक्तूबर को इन्हीं आतंकियों की तलाश भाटादूड़ियां के जंगल तक की गई।

आतंकी तो नहीं मिले, लेकिन चार जवान और बलिदान हो गए। दो महीनों तक इन आतंकियों की आसमान और जमीन पर ड्रोन, हेलिकॉप्टर से तलाश की गई। लेकिन एक भी आतंकी का पता नहीं लगा और सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया। यह सिलसिला अब तक जारी है।

पूर्व सैनिक निकलें अपने घरों से

अब हमें भी बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे पूर्व सैनिकों को आगे आना होगा। सरकार को चाहिए कि इन्हें हथियार मुहैया कराए। खासकर राजोरी, पुंछ, डोडा, कठुआ में तैनात रह चुके स्थानीय सैन्यकर्मियों को अपने साथ जोड़ें। यह आतंकियों के खात्मे के लिए मददगार साबित होंगे।

– गोवर्धन सिंह जमवाल, पूर्व जनरल

हमले बर्दाश्त नहीं, कुछ बड़ा करने की जरूरत

कुछ बड़ा करने की जरूरत है। यह जल्दी होना चाहिए। ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं। जंगलों में छिपे आतंकियों पर कार्रवाई के लिए आधुनिक संचार नेटवर्क, खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। – **एसपी वैद,** पूर्व डीजीपी

जम्मू संभाग में बड़े आतंकी हमले

- 11 अक्तूबर 2021, चमरेल पुंछ,5 जवान शहीद
- 14 अक्तूबर 2021, भाटादूड़ियां, 4 जवान शहीद
- 20 अप्रैल 2023, भाटादूड़ियां, 5 जवान शहीद
- 5 मई 2023, केसरी पर्वत राजोरी,5जवान शहीद
- 22 नवंबर 2023, कालाकोट राजोरी, दो अफसर सहित 4 शहीद
- 8 जुलाई 2024, कठुआ, पांच जवान बलिदान
- 15 जुलाई 2024, डोडा, चार जवान बलिदान

हिंदू नागरिकों पर दो बड़े हमले

आतंकियों ने हिंदू समुदाय के नागरिकों पर भी हमले किए हैं। पहला हमला वर्ष 2023 में 1 जनवरी को राजोरी के ढांगरी गांव में किया गया। इस हमले में 7 हिंदू नागरिकों की हत्या कर दी गई। इसके बाद 2024 में 9 जून को रियासी जिले में एक बस पर आतंकवादी हमले में 10 यात्रियों की हत्या की गई।

सात माह में 12 सुरक्षाकर्मी, 10 नागरिकों की मौत

जम्मू संभाग में पिछले 7 माह से अब तक आतंकी हमलों में सैन्य कैप्टन सहित 12 सुरक्षाकर्मी बलिदान हो गए। हमलों में 10 नागरिक मारे गए हैं, जबकि 55 लोग घायल हुए हैं। वहीं पांच आतंकी मारे गए।

हरियाणा में नहीं होगी भाजपा की हैट्रिक, जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी

नई दिल्ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने मंगलवार को राजधानी में संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और इस साल के अंत में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले एकता का वादा किया। मुलाकात के बाद दिग्गज कांग्रेस नेता ने कहा कि हम हरियाणा चुनाव मजबूती से जीतेंगे।% इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य की सभी 36 कौमें कांग्रेस के पीछे एकजुट हो गई हैं और उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार देने में विफल रही है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने कोई विकासात्मक कार्य नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। उन्होंने दावा किया कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप घोषणापत्र तैयार किया जाएगा। आने वाले चुनाव में हरियाणा की जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह रुझान लोकसभा चुनावों में दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस ने 2019 में शून्य के मुकाबले राज्य के दस संसदीय क्षेत्रों में से पांच पर जीत हासिल की। यह पूछे जाने पर कि क्या वह राज्य इकाई में गुटबाजी को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, हुड्डा ने कहा कि रैंकों में कोई मतभेद नहीं है। राज्य में कांग्रेस के प्रचार अभियान के प्रमुख चेहरे के रूप में देखे जाने वाले पूर्व सीएम ने कहा, हम सभी एकजुट हैं और एक साथ चुनाव में उतरेंगे, हालांकि उन्हें राज्य की एक और मजबूत नेता कुमारी शैलजा से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी, जिन्होंने हाल ही में सिरसा लोकसभा चुनाव में पूर्व राज्य कांग्रेस प्रमुख अशोक तंवर को हराकर बड़ी जीत हासिल करके अपनी ताकत साबित की थी।

हुड्डा ने यह भी कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारों के नामांकन की तैयारी शुरू कर दी है और संभावित उम्मीदवारों से जुलाई के अंत तक टिकट के लिए आवेदन करने को कहा है। हरियाणा में दो बार से सत्ता पर काबिज सत्तारूढ़ बीजेपी की नजर इस बार हैट्रिक लगाने पर है। हरियाणा में इस वर्ष के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सोमवार को 'हरियाणा मांगे हिसाब' अभियान शुरू किया। विपक्षी दल ने कहा कि अभियान के तहत वह बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था सहित विभिन्न मोर्चों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निशाना बनाएगी।

हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

22 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखने की मांग की है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग भी की है। अब जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगी। हरियाणा सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करने के मद्देनजर उसने रास्ता बंद रखा हुआ है। हाई कोर्ट को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए। इसके अलावा, हालांकि हरियाणा सरकार ने स्वीकार किया कि सीमा बंद होने के कारण आम जनता को असुविधा हो रही थी, लेकिन उसने उच्च न्यायालय के आदेश के एक हिस्से की ओर इशारा किया, जिसमें दर्ज है कि %400 से 500 ट्रॉलियां% और %50 से 60 अन्य वाहन% %लगभग 500 आंदोलनकारियों का जमावड़ा% अभी भी स्थल पर डेरा डाले हुए था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ मंगलवार को एक दिन पहले दायर की गई हरियाणा की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को 22 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई। सीमा 13 फरवरी से बंद है, जिस दिन पंजाब के कई किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर मार्च शुरू किया था।

21 जुलाई को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, राहुल हो सकते हैं शामिल

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। मोदी सरकार के लिए दोबारा सत्ता में आने के बाद यह पहली बड़ी परीक्षा होगी। यही कारण है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई को सुबह 11 बजे मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, दिल्ली में होगी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन, सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो सकता है। विशेष रूप से, यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पहली अपेक्षित उपस्थिति है। बैठक का उद्देश्य आगामी सत्र के लिए प्रमुख एजेंडों और रणनीतियों पर चर्चा करना है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने पुष्टि की कि बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। उन्होंने 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में उद्धृत किया, जो 1993 में कोलकाता पुलिस गोलीबारी की घटना के दौरान दुखद रूप से मारे गए 13 कांग्रेस समर्थकों की याद में हर साल मनाया जाता है। यह घटना पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार के तहत राज्य सचिवालय, राइटर्स बिल्डिंग तक मार्च के दौरान हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट (2024-25) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी। संसद सत्र एक दिन पहले शुरू होगा और 12 अगस्त को समाप्त होगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स लिखा था कि भारत के राष्ट्रपति ने, भारत सरकार की सिफारिश पर, 22 जुलाई, 2024 से 12 अगस्त, 2024 तक बजट सत्र, 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई, 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। विशेष सत्र के दौरान संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि आने वाला बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य की दृष्टि का एक प्रभावशाली दस्तावेज होगा और इसमें कई ऐतिहासिक कदम और प्रमुख आर्थिक/सामाजिक कदम होंगे। निर्णय लिये जायेंगे।

प्रमुख समाचार

नीट यूजी काउंसलिंग 20 जुलाई को

नई दिल्ली। नीट यूजी विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने काउंसलिंग जल्द शुरू करने का संकेत दिया है। मंत्रालय की ओर से एक नोटिस जारी कर मेडिकल कॉलेजों से सीटों का विवरण दर्ज करने के लिए कहा गया है। नोटिस में मेडिकल कॉलेजों को आधिकारिक पोर्टल – mcc.nic.in पर अपनी सीटें दर्ज करने के लिए आमंत्रित किया गया है। समिति इंट्राएमसीसी पोर्टल पर यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए भाग लेने वाले संस्थानों से 20 जुलाई तक सीट का विवरण स्वीकार करेगी। लाखों की संख्या में छात्र नीट यूजी काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में एमसीसी द्वारा मेडिकल कॉलेजों से सीट का विवरण मांगना यह दर्शाता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द ही शुर कर दी जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुलाई के तीसरे सप्ताह से नीट यूजी के काउंसलिंग की बात की थी। एमसीसी द्वारा जारी नोटिस में लिखा है, यूजी काउंसलिंग 2024 में भाग लेने वाले संस्थानों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि यूजी सीटों के योगदान के लिए इंट्रामेस पोर्टल अब खुला है।

बिभव कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र उस दिन दायर किया गया था जब तीस हजारी कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 30 जुलाई तक बढ़ा दी थी और जेल अधीक्षक को सुनवाई की अगली तारीख पर उन्हें शारीरिक रूप से पेश करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया था कि केजरीवाल के आवास पर सुरक्षा कर्मचारियों को गवाह बनाकर 1,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है। पुलिस ने मुख्यमंत्री के आवास से डीवीआर भी एकत्र कर लिया है और कुमार के दो मोबाइल फोन सहित कई गैजेट जब्त कर लिए हैं। कुमार को उनके मोबाइल फोन से कथित रूप से हटाए गए डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए पुलिस हिरासत के दौरान दो बार मुंबई ले जाया गया था। लीवाल ने एफआईआर में बिभव कुमार पर आरोप लगाया था कि जब वह 13 मई को केजरीवाल के आवास पर गई थीं.

पूजा खेडकर को ऑन जॉब ट्रेनिंग से बुलाया

नई दिल्ली। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर बड़ा एक्शन हुआ है। पूजा खेडकर की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने ऑन जॉब ट्रेनिंग से वापस बुला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूजा को मसूरी के ट्रेनिंग अकेडमी में वापस बुलाया गया है। 23 जुलाई तक पूजा खेडकर को रिपोर्ट करने के लिए कह दिया गया है। खेडकर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए कथित तौर पर फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के मामले में जांच के दायरे में हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी ने एक पत्र में कहा कि उसने पूजा दिलीप खेडकर के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोकने का फैसला किया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए तत्काल वापस बुला लिया है। सूत्रों के अनुसार, प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने पुणे कलेक्टर डॉ. सुहास दिवसे के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है, जिन्होंने सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों के बाद पुणे से उनका स्थानांतरण शुरू किया था। खेडकर को पिछले सप्ताह अतिरिक्त सहायक कलेक्टर के रूप में काम करने के लिए पुणे से वाशिम स्थानांतरित किया गया था।

शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद कविता की बिगड़ी तबीयत

नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता को मंगलवार शाम दिल्ली के डीडीयू अस्पताल ले जाया गया। वह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जेल में हैं। के कविता को इस साल 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। छह दिन बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार कर लिया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया। इस महीने की शुरुआत में, के कविता ने अब खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया। के कविता को सबसे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। अगले महीने, सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी है।.

न्यायाधीशों ने संविधान को आघात से बचाया: मेघवाल

प्रयागराज । केन्द्र सरकार के 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' अभियान के यहां दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने देश में 1975 में लगे आपातकाल को याद दिलाते हुए मंगलवार को कहा कि इसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने संविधान को आघात से बचाया। यहां एएमए के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेघवाल ने कहा, यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही था.. इस संविधान पर 1975 में ही सबसे ज्यादा चोट पड़ी थी। अदालत के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा के साहस को सभी याद करते हैं। संविधान पर आघात की कोशिश जरूर हुई होगी,लेकिन न्यायमूर्ति सिन्हा और न्यायमूर्ति एच आर खन्ना ने संविधान का सम्मान बराबर रखा। उन्होंने कहा कि भारत के आसपास कई देश हैं जहां सेना के हाथ सत्ता गई, गृह युद्ध भी हुए। लेकिन भारत अपने संविधान के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया और लोग सुरक्षित रहे। इसका एक ही कारण है भारत का संविधान। मेघवाल ने कहा, भारत के इसी संविधान के तहत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया ने काम किया.

नेपाल से चटके रिश्ते ठीक करना बड़ी चुनौती

राजेश बादल

नेपाल में फिर नई सरकार बन गई. के. पी. शर्मा ओली चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए. उनके पुराने कार्यकाल को याद करें तो भारत के लिए यह कड़वाहट भरा था. ओली ने भारत के साथ वह बरताव किया था, जो अब तक वहां के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था. वे चीन की गोद में बैठकर भारत को धमकी दे रहे थे कि एक इंच जमीन भी भारत को नहीं देंगे. लेकिन वे भूल गए थे कि उनके देश का भारत के साथ रोटी-बेटी का रिश्ता है. वे नेपाल की सियासत में जिद्दी अधिनायक जैसे हैं, जो झटके खाने के बाद भी सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं. अभी भी उन पर चीन का प्रभाव है. जाहिर है यह स्थिति नेपाल को स्थिर लोकतंत्र की तरफ नहीं ले जाती. अरसे से चल रही राजनीतिक अस्थिरता ने भारत के इस पड़ोसी पहाड़ी मुल्क का बड़ा नुकसान किया है. भारत के लिए यह कठिन कूटनीतिक समीकरण बनाती है.

इसलिए कहना आसान नहीं है कि आने वाले दिन नेपाल और हिंदुस्तान के बीच चटके रिश्तों में शहद घोलेंगे और इस छोटे से देश में सियासी स्थिरता आएगी. संदर्भ के तौर पर बता दूं कि राजशाही समाप्त होने के बाद अब तक नेपाल के किसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है. अब तक 11 प्रधानमंत्री पद संभाल चुके हैं. करीब दो साल पहले इसी पन्ने पर मैंने नेपाल में सियासी स्थिरता को लेकर अपनी आशंकाएं प्रकट की थीं. मैंने लिखा था कि छोटे-छोटे दलों से मिलकर बनी प्रचंड की खिचड़ी सरकार शायद ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए. चिंता की बात यही है कि यह राजनीतिक अस्थिरता भारत का सिरदर्द बढ़ाने वाली है. सूत्रों का कहना है कि इस बार भी चीन के दूतावास ने ओली को प्रधानमंत्री बनाने में परदे के पीछे से बड़ी भूमिका निभाई है. भारतीय दूतावास चाहता तो नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने में सहायता कर सकता था. देउबा हमेशा भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने के पक्ष में रहे हैं. इसे भारतीय दूतावास की कूटनीतिक कमजोरी भी माना जा सकता है. चिंता की बात यह है कि ओली एक बार फिर सीमा विवाद को हवा दे सकते हैं. कौन भूल सकता है कि ओली के पिछले कार्यकाल में ही भारत और नेपाल के बीच सीमा पर पहली बार बॉर्डर पोस्ट बनाए गए और नेपाली पुलिस ने भारतीयों पर गोलियां चलाई थीं.

ओली ने ही कहा था कि भारत कालापानी से अपने सैनिक वापस बुलाए वरना नेपाल अपनी जमीन खाली कराना भी जानता है. कालापानी के अलावा नेपाल ने लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी अपना इलाका बताया था. कालापानी की स्थिति कुछ-कुछ डोकलाम जैसी है. जब डोकलाम में चीन की दाल नहीं गली तो उसने नेपाल में भारत विरोधी जनआंदोलन को हवा दी. कुछ साल पहले नेपाल में भारत विरोधी आंदोलन तेज हो गए थे. इन प्रदर्शनों में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ-साथ नेपाली कांग्रेस भी शामिल थी, जो अभी ओली सरकार को समर्थन दे रही है. कालापानी में 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद से ही भारतीय सेना तैनात है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विभाजन के बाद हिंदुस्तान का नया नक्शा जारी किया गया था. इसमें कालापानी को भारत में बताया गया है. कालापानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में करीब पैंतीस किलोमीटर की पट्टी है. काली नदी यहीं से निकलती है. नेपाल कहता है कि यह उसका क्षेत्र है. इसका आधार वह 1961 में कराई गई जनगणना को बताता है. नेपाल का तर्क है कि उस समय भारत ने कोई ऐतराज नहीं दर्ज कराया था, इसलिए भारत वह पट्टी खाली करे. भारत और नेपाल के रिश्ते अतीत में कितने ही मधुर रहे हों लेकिन हकीकत तो यही है कि बीते दस साल में नेपाल चीन के करीब गया है.

दरअसल 2015 में जब नेपाल ने अपना नया संविधान लागू किया तो भारत ने चाहा था कि उसमें मधेशियों और थारू समुदायों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले. नेपाल ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना था और विरोध जताया था. उसने आपत्ति जताई थी कि दिल्ली से गए विदेश मंत्रालय के एक आला अफसर काठमांडू में बैठकर नेपाल के अफसरों और राजनेताओं को निर्देश दे रहे हैं. यह अलग बात है कि जब चीन का दूतावास काठमांडू में ऐसी हरकत करता है तो वह चुप्पी साधे रहता है. नेपाल मौटे तौर पर पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में बंटा है. तराई में मधेशी और थारू जनजाति के लोग हैं, जो भारत समर्थक माने जाते हैं. पहाड़ी इलाके में बसे नेपाली चीनी प्रचार का शिकार बने हैं. उनसे कहा गया है कि भारत नेपाल पर कब्जा करना चाहता है. इसके बाद जब मधेशियों ने अपना आंदोलन छेड़ा तो भारत से जाने वाला सामान रुक गया. नेपाल ने इसे भारतीय आर्थिक नाकेबंदी माना और भारत की छवि बिगड़ने का प्रयास हुआ. इन्ही दिनों नेपाल में जब भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई तो भारत ने ताबड़तोड़ वैसी ही सहायता दी थी, जैसी वह अपने ही किसी प्रदेश को पहुंचाता.

चीनी प्रोपेगंडा के तहत एक बार फिर प्रचारित किया गया कि भारत नेपाल में विस्तारवादी नीतियों के साथ दाखिल हो रहा है. अफसोस की बात है कि नेपाल के नौजवान इन पर भरोसा करते दिखाई दे रहे हैं. अलबत्ता नेपाली कांग्रेस अभी भी कहीं-कहीं ओली से फासला बनाती दिखाई दे जाती है, पर अब वह ओली के साथ है. देखना दिलचस्प होगा कि पिछले बरस पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के एक बयान से सियासत गरमा गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में भारतीय मूल के एक नेपाली सिख व्यापारी की बड़ी भूमिका रही है.

जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक, धान घोटाले में मजदूरों पर एफआईआर का विरोध

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत के सभा कक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष निशा नेताम, उपाध्यक्ष राधा सिंह देव,विधायक उद्धेश्वरी पैकरा जिला पंचायत सीईओ रैना जमील सहित जिला पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित किया गया जिसमें खाद्य बीज समय पर किसानों को उपलब्धता समय पर सुनिश्चित कराने, चिकित्सकों के समय पर स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थित होने, जल जीवन मिशन के कार्यों में बरती जा रही है अनियमितता, अवैध कटाई से खाली पड़े वन भूमि पर वृक्षारोपण करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा पूरे जिले में खाद्य बीज समय पर उपलब्ध कराने की बात प्रमुखता से उठाई जिस पर उपसंचालक कृषि को समय पर खाद बीज किसानों को समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए वहीं समय पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में खाद्य बीज के वितरण के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत के सदस्य अंकुश सिंह सामरी क्षेत्र में ने हिंडालको के द्वारा बॉक्साइट परिवहन से प्रधानमंत्री सड़क योजना के सड़कों की दुर्दशा होने की बात प्रमुखता से उठाई जिस पर हिंडालको से समन्वय स्थापित कर प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता को सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत के सदस्य राजेश यादव ने ग्राम पीपरोल, मितगई, पुरुषोत्तमपुर, विजयनगर, देवगई, देवीगंज सहित अन्य गांव

में वनों की अवैध कटाई से खाली पड़े वन भूमि पर वृक्षारोपण कराए जाने की बात उठाई।

बैठक में जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में समय पर चिकित्सकों के उपस्थित सुनिश्चित करने की बात उठाई। जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सदस्य पुष्पा नेताम,विनोद जायसवाल, राजेश यादव अंकुश सिंह, राम चरित्र सोनवानी, विजेता तिर्की,गीत सोनहा, अनीता मिंज सहित जिला पंचायत के अन्य सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला पंचायत के सदस्य राजेश यादव ने सामान्य सभा की बैठक में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति भवरमाल एवं विजय नगर में हुई धान घोटाले के मामले में खरीदी प्रभारी के साथ-साथ करीब 20 मजदूरों के नाम से भी एफआईआर दर्ज किया गया। जिसे उन्होंने जमकर विरोध किया उन्होंने कहा कि कार्यवाही सख्त से सख्त खरीदी प्रभारी के विरुद्ध होनी चाहिए मजदूरों को इतिहास में पहली बार आरोपी बनाकर एफआईआर किया गया। मजदूरों पर एफआईआर होने के बाद उनके परिवार जनों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है जो मजदूर का कार्य करते थे उनको आरोपी बनाया जाना बिलकुल ही न्यायोचित नहीं है।

कार्यपालन अभियंता की कार्य प्रणाली पर उठे सवाल

जिला पंचायत के सदस्य राजेश यादव एवं अंकुश सिंह के द्वारा जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया साथ ही साथ उन्होंने तात्कालिक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता के कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि पूरे जिले में जल जीवन मिशन का कार्य संतोषप्रद नहीं है बिहार से आए ठेकेदारों के द्वारा जमकर मनमानी की जा रही है जिस प्रकार से जिले में जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है उससे उसका लाभ लोगों को नहीं मिल सकेगा।

विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने शिविर का आयोजन

बलौदाबाजार। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश में जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों को चिन्हांकित कर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित एवं पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। शिविर में शासकीय अधिकारी- कर्मचारियों द्वारा लोगों को विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग हेतु संचालित योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

इसी कड़ी में कमार जनजाति निवासरत कसडोल विकासखंड अंतर्गत ग्राम बल्दाकछार एवं अवराई में शिविर का आयोजन किया गया। उक्त दोनों गांव के शिविर में 1 का नया आधार

कार्ड,6 नवीनीकरण,18 आयुष्मान,7 जनधन खाता, 4 नए राशन कार्ड, पीएमकिसान सम्मान निधि के तहत 34 हितग्राहियों का पंजीयन, 15 श्रम कार्ड बताएं गए है। साथ ही 22 श्रम कार्ड का नवनीकरण किया गया है। इसके साथ ही 6 जाति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। गौरतलब है कि पीएम जनमन योजना का मूल उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), परिवारों और बस्तियों तक बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को पहुंचाकर उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। पीएम जनमन योजना अंतर्गत कमजोर जनजाति समूहों के बसाहटों में विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सड़क, आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण, आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। शिविरों में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के वंचित लोगों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जनधन खाता, केसीसी, जाति प्रमाण पत्र,वन अधिकार पत्र, जॉब कार्ड सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण के रूप मंध बीपी, शुगर, आंख, खून की जांच कर आवश्यक परामर्श एवं दवाइयां भी प्रदान की जा रही है। विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को शिविर तक लाने हेतु महिला कर्मचारियों, स्वसहायता समूह द्वारा सहयोग भी किया जा रहा है।

आज से नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों पर होगी कार्रवाई

बिलासपुर। यात्रियों के वाहनों की बेहतर यातायात व्यवस्था के साथ ही एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु रेलवे प्रशासन प्रतिबद्ध है।यात्रियों के वाहनों की व्यवस्थित व सुरक्षित पार्किंग हेतु पार्किंग स्टैंड का प्रावधान किया गया है, जिससे वे निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अपने वाहनों को खड़ा कर निश्चिंत रह सके।

पार्किंग के लिए अधिसूचित स्थानों के अलावा ज़ीरो गेट से स्टेशन चौक, आरक्षण कार्यालय भवन से चुचुहिया आरयूबी तक, स्टेशन चौक से तितली चौक एवं रेल्वे कोच रेस्टोरेन्ट से महेश स्वीट्स तक रेलवे क्षेत्र को नो पार्किंग क्षेत्र घोषित किया गया है ताकि स्टेशन परिसर में यात्रियों के व्यवधान रहित आवागमन तथा स्टेशन का सौदर्यीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

वरि.मंडल वाणिज्य प्रबन्धक श्री अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में नागरिक सुरक्षा संगठन स्पेशल सेल के टीम द्वारा

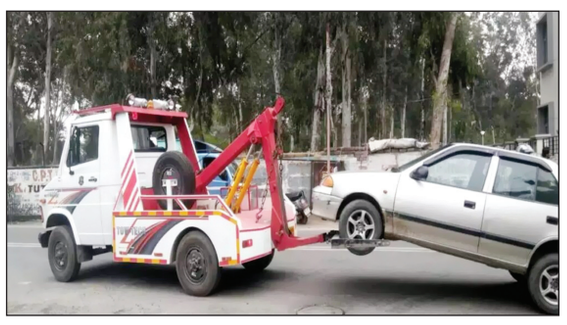

जागरूकता अभियान चला कर यात्रियों व उनके परिजनो को नो पार्किंग क्षेत्र में गाड़ी नहीं खड़ी करने की समझाइस दी जा रही है। रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि दिनांक 17 जुलाई 2024 से नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी दो-तीन पहिया गाडियों को उठाकर एक निर्धारित स्थान गेट नं 04 के आगे टीआरडी ऑफिस के पास से गाड़ी को खींच कर ले जाया जाएगा। इन गाडियों को 200 रुपये शुल्क का भुगतान करने के बाद ही छोड़ा जाएगा, 06 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अतिरिक्त 20 रुपये प्रतिघंटे की दर से शुल्क की वसूली की जाएगी। इसी प्रकार नो पार्किंग में खड़ी चार पहिया वाहनों को वहीं पर क्लेंपिंग किया जाएगा तथा 500 रुपये शुल्क का भुगतान करने पर ही छोड़ा जाएगा, इसके अलावा 06 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अतिरिक्त 50 रुपये प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त शुल्क की वसूली होगी। शुल्क की रसीद इस कार्य के प्रभारी रेलवे कर्मचारी द्वारा दिया जाएगा।वाहनों को नहीं ले जाने की स्थिति में रेलवे नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

4 हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान में सुरक्षाबलों को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत 8 लाख के इनामी नक्सली कैलाश उर्फ कवासी देवा, जो नक्सल संगठन की कंपनी नंबर 10 में डिप्टी कमांडर पद पर था, इसके साथ 5-5 लाख के दो नक्सली और एक 2 लाख के इनामी नक्सली ने सुकमा के एसपी किरण चव्हाण के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। कुल 20 लाख के इनामी 4 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 2 महिला नक्सली और 2 पुरुष नक्सली शामिल हैं। सुरक्षाबलों

के लगातार दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति के चलते नक्सल ग्रस्त सुकमा जिले के नक्सली आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बड़े कैडर के नक्सलियों के आत्मसमर्पण का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार की पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिय जावेगा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आत्मसर्पित चारों नक्सली जिले में कई बड़े वारदातों में शामिल रहे हैं और उनके आत्मसमर्पण से सुरक्षाबलों को तथा नक्सल इलाकों के ग्रामीणों को राहत मिलेगी।

बारिश में बह गई सड़क, छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश जाने का रास्ता बंद

गौरेला-पेंड्रा। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय होने से पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में गौरेला से अमरकंटक जाने वाली सड़क बारिश में बह गई है। इसके चलते छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश का रास्ता बंद हो गया है, जिसके कारण पिछले 14 घंटे से आवाजाही ठप है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश से पेंड्रा में ज्वालेश्वर घाट में चुकतीपानी के पास सड़क बही है। नाले के ऊपर वैकल्पिक रूप से बनाया गया पुल भी बह गया है। मौसम विभाग ने आज भी कांकेर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कबीरधाम, बेमेतरा के लिए ऑरेंज अलर्ट और धमतरी, गरियाबंद, कोंडगांव, नारायणपुर और राजनांदगांव के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 248.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से 15 जुलाई सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 410.7 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 135.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है।

24 घंटे के अंदर मिली जशपुर अंचल को एंबुलेंस और शव वाहन

मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल, प्रदेश में तेजी से सुधर रही है स्वास्थ्य सेवाएं

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के घोषणा के अनुरूप स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जशपुर जिले को दो बड़ी सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने सीएम कैंप बगिया में दो एंबुलेंस और एक शव वाहन को हरी झंडी दिखा कर जरूरतमंद मरीजों की सेवा के लिए रवाना किया। एंबुलेंस दुलदुला ब्लॉक के करडेगा और फरसाबहार ब्लाक के कोल्हेनझरिया में सेवा देगी। वहीं मुक्तांजली वाहन दुलदुला में सेवा प्रदान करने के लिए तैनात रहेगी।

उल्लेखनीय है कि एक दिन

पहले ही रविवार को दुलदुला में आयोजित मतदाता अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की थी। घोषणा के 24 घंटे से भी कम समय में ही जिलेवासियों को एम्बुलेंस और शव वाहन की सुविधा मिली है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय की पहल से दिसंबर 2023 से अब तक जिले को 7 एंबुलेंस और 1 शव वाहन मिल चुके हैं। इससे मरीजों की सेवा में लगे एंबुलेंस की संख्या जिले में बढ़ कर 21 हो चुकी है। इसके साथ ही कुनकुरी में 220 बिस्तर की क्षमता वाली सर्वसुविधा युक्त अस्पताल निर्माण की घोषणा पहले ही हो चुकी है। जिले के 7 उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा देते हुए आवश्यक मानव संसाधन जुटाने के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

अवैध रूप से भंडारण करने पर 500 बोरी जैविक खाद जप्त

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिले में उर्वरक निगरानी टीम द्वारा छापामारी के दौरान पेंड्रा विकासखंड के ग्राम पंचायत सरखोर में अवैध रूप से भंडारण करने पर 500 बोरी जैविक खाद जप्त किया गया है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी के निर्देशानुसार खाद-बीज की कालाबाजारी रोकने एवं अवैध भंडारण की जांच-पड़ताल एंव कार्रवाई के लिए टीम गठित किया गया है। जांच दल ने आज ग्रामीणों द्वारा प्राप्त सूचना पर ग्राम सरखोर में छापामार कार्यवाही किया, जहां सहसराम के घर पर मेसर्स संतोष राठौर पेंड्रा द्वारा अवैध रूप से 500 बोरी जैविक खाद का भंडारण कराया जा रहा था। मौके पर कृषि विभाग की टीम द्वारा आवश्यक पूछ-ताछ कर दस्तावेज मांगा गया। समाधान कारक उत्तर एवं दस्तावेज नहीं देने के कारण उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत 500 बोरी खाद को जप्त कर घर में ही सीज कर दिया गया है। इस कार्यवाई में कृषि विभाग के उप संचालक सत्यजीत कंवर, अनुविभागीय अधिकारी एस एस आर्मो और उर्वरक निरीक्षक हेमंत कश्यप शामिल थे।

पुलिस की जुआ एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, आठ गिरफ्तार

कबीरधाम। बीती रात को कबीरधाम पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई कवर्धा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम ग्राम सोनपुरी (रानी सागर) में की गई है। मौके से पुलिस ने तीन बाइक, 8 मोबाइल व 2.31लाख रुपए नगद समेत 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बीती रात को कबीरधाम पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई कवर्धा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम ग्राम सोनपुरी (रानी सागर) में की गई है। मौके से पुलिस ने तीन बाइक, 8 मोबाइल व 2.31लाख रुपए नगद समेत 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दो आरोपी रायपुर व दुर्ग जिले के थे, जो यहां जुआ खेलने के लिए पहुंचे थे। एडिशनल एसपी पुष्पेन्द्र सिंह बघेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम सोनपुरी (रानी सागर) के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई किया। इस दौरान कई आरोपी पुलिस को आते देख भाग गए।

पियक्कड़ शिक्षक पर एक्शन स्कूल में शराब पीकर पहुंचा

कबीरधाम। शराब पीकर स्कूल पहुंचे शिक्षक को कलेक्टर के निर्देश पर सस्पेंड कर दिया गया है। मामला कबीरधाम जिले के शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम महराजपुरडीह का है। इसे लेकर सोमवार देर रात आदेश जारी किया गया है। जानकारी अनुसार कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी वाईडी साहू ने विकासखण्ड बोड़ला अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम महराजपुरडीह के सहायक शिक्षक (एलबी) फत्ते सिंह धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन की यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर हुई। आदेश में बताया गया है कि शिक्षक फत्ते सिंह धुर्वे छह अक्तूबर 2023 से चार अप्रैल 2024 तक अनुपस्थित रहते हुए नौ अप्रैल 2024 को मेडिकल अनफिट व फिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। चार जुलाई 2024 से दस जुलाई 2024 तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहे है। इसके बाद 11 जुलाई 2024 को सुबह 11.45 बजे शराब पीकर स्कूल में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त हुई।

नशे में बेटा बना जल्लाद, मां से मांग रहा था पैसा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। शराबी कलयुगी बेटे ने शराब के लिए पैसा नहीं देने पर अपनी मां को फावड़े के बेंत से बेरहमी से पीट-पीटकर उसका एक हाथ और एक पैर तोड़ डाला। जिसके बाद दर्द से कराह-कराह कर उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ 103-बीएनएस का अपराध दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। मां की बेरहमी से हत्या का पूरा मामला जिले के गौरेला थानाक्षेत्र के सारबहरा गांव के बहेलिया टोला का है। जहां पर रहने वाली रोशनी बाई की उसी के बेटे अर्जुन सिंह भैना ने फावड़े के बेट से पीट-पीटकर हत्या कर दी है। रोशनी बाई अपने बेटे अर्जुन सिंह और अर्जुन की पत्नी के साथ रहती थी। घटना के दिन भी घर में थी और घर के बाकी सदस्य खेतों में फसलों की बोवाई में व्यस्त थे। उसी समय रोशनी बाई अपने घर से भागते हुए अपने पड़ोसी के घर के बाड़ी में आई और बचाव-बचाव चिल्ला रही थी। उसी के पीछे-पीछे उसका शराबी बेटा अर्जुन सिंह भैना भी पड़ोसी के घर पहुंचा।

जांजगीर में रफ्तार का कहर मालवाहक वाहन दुकान में घुसा

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के हरदीविशाल में तेज रफ्तार मालवाहक माजदा वाहन सड़क किनारे दुकान के अंदर जा घुसा। हादसे में दुकानदार युवक अशोक कुमार बनर्जी 43 वर्ष की मलबे में दबने से मौत हुई है। दुकान में समान लेने आया युवक और ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृत के परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर चक्का जाम किया गया है। बलौदा थाना क्षेत्र की घटना है। मिली जानकारी अनुसार, अशोक कुमार बनर्जी जोकि एनटीपीसी कंपनी में निजी कर्मचारी था। आज मंगलवार की सुबह 7 बजे अपने सड़क किनारे दुकान में बैठा हुआ था वही उसका एक चचेरा भाई समान लेने भी आया हुआ था। इस दौरान मालवाहक माजदा वाहन के चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया तेज रफ्तार से होने के कारण सीधे दुकान के अंदर जा घुसी। दुकान संचालक अशोक कुमार बनर्जी की दुकान के मलबे में दब गया। मलबे से निकलकर अस्पताल लेकर पहुंचे जहा डॉक्टर ने मृत घोषित किया। वही ड्राइवर का इलाज जिला अस्पताल जांजगीर में चल रहा है।

19 ग्रामीणों से लाखों रुपये लेकर बांट दिए वन अधिकार पट्टा

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में वन विभाग के भूमि को फर्जी तरीके से ग्रामीणों को दिए जाने का मामला सामने आया है। मामला जिले के नक्सल प्रभावित थाना रेंगाखार जंगल का है। इस क्षेत्र के 8 गांव के 19 ग्रामीणों से 3.34 लाख रुपए लेकर चार आरोपी ने फर्जी तरीके से वन अधिकार पट्टा बाट दी। अब शिकायत बाद दो आरोपी गिरफ्तार है। वहीं दो फरार है, जिसके बारे में पतासाजी की जा रही है। एडिशनल एसपी पुष्पेन्द्र सिंह बघेल ने बताया कि मामले में वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी रेंगाखार के प्रतिवेदन के आधार पर वनपाल प्रीतम दास मानिकपुरी वन परिक्षेत्र रेंगाखार के रिपोर्ट पेश किया गया।

29 जून को फर्जी वन अधिकार पट्टा 19 ग्रामीणों के नाम पर बनाकर वितरण कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी मन्नूलाल पिता रामदयाल कुशरे उम्र 34 वर्ष निवासी मुढ़ीपार थाना रेंगाखार, मुकेश यादव पिता भीमूलाल यादव उम्र 32 वर्ष निवासी

नगवाही थाना रेंगाखार, देवीलाल कुशरे निवासी रेंगाखार नयाबाड़ा, रामकुमार यादव निवासी मुढ़ीपार के खिलाफ धारा 420, 467, 468 ,471व 34 के तहत मामला दर्ज किया। इन शातिर आरोपियों ने ग्रामीणों से अवैध वसूली कर फर्जी कलेक्टर, वन मडण्लाधिकारी, सहायक आयुक्त का फर्जी हस्ताक्षर व सील लगाकर क्षेत्र के 8 गांव के 19 लोगों को वन अधिकार पट्टा बाट दिया।

इन ग्रामीणों से 5 से 40 हजार रुपए लिए गए थे। ओरवरऑल 19 ग्रामीणों से 3 लाख 34 हजार रुपए लेकर पट्टा बाट दिया था। वन विभाग को जानकारी मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी मन्नूलाल व मुकेश यादव को गिरफ्तार किया है। इन्हे आज मंगलवार 16 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दो अन्य आरोपी देवीलाल कुशरे निवासी रेंगाखार नयाबाड़ा व रामकुमार यादव निवासी ग्राम मुढ़ीपार का फरार है। इनके बार मे पतासाजी की जा रहीं है। बता दे कि जंगल क्षेत्र में लोगों को कृषि कार्य के लिए भूमि दी जाती है। जिसे वन अधिकार पट्टा कहा जाता है। इस पट्टे की भूमि से कृषि कार्य किया है, जिसकी निश्चित अवधि भी तय रहती है।

केते एक्सटेंशन के समर्थन में उतरे ग्रामीण

- **कलेक्टर को ज्ञापन सौंप नौकरी, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार का दिया हवाला**

अंबिकापुर। जिले के उदयपुर ब्लॉक में स्थित केते एक्सटेंशन कोल परियोजना की जनसुनवाई के समर्थन में प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने सोमवार को सरगुजा कलेक्टर और क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि केते एक्सटेंसन कोल ब्लॉक के संचालन से यहां पर हजारों लोगों को नौकरी, स्व-रोजगार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा।

ग्राम परसा, साल्ही, हरिहरपुर इत्यादि गांव के 100 से अधिक ग्रामीण हस्ताक्षरित ज्ञापन देने 15 जुलाई को अंबिकापुर कलेक्टर और क्षेत्रीय

पर्यावरण कार्यालय पहुंचा। इस दौरान मौजूद ग्राम परसा की मीरा बघेल, सरपंच झल्लूराम सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि,हम सभी ग्रामवासी 2 अगस्त को केते एक्सटेंशन के लिए हमारे गांव परसा में होने वाले पर्यावरणीय जन सुनवाई का समर्थन करते हैं, और इसे तय समय में पूरी कराने की मांग करते हैं। ज्ञापन में ग्राम परसा, घाटबर्रा, हरिहरपुर, जनार्दनपुर इत्यादि गांव के ग्रामीणों ने लिखा है कि राजस्थान राज्य विद्युत की कोयला खदान जब से हमारे क्षेत्र में खुली हैं तब से नौकरी और स्वरोजगार सहित गावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ढांचागत विकास के कई कार्यक्रम संचालित हैं। जिससे हमें विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का मौका मिला हैं। साथ ही हम तमाम जन प्रतिनिधि एवं ग्रामवासी चाहते है कि परियोजना आए और क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाय, जिससे क्षेत्र का बहुमुखी विकास हो सके। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी तथाकथित एनजीओ गांव के सीधे-साधे ग्रामवासियों को बहलाकर जन सुनवाई के विरोध में प्रशासन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की बात कही जा रही है। हम ग्रामवासियों का परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सुनवाई के लिए किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। ग्रामीणों ने केते एक्सटेंसन कोल ब्लाक के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन कराने की मांग की है।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री से पर्वतारोही निशु सिंह ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से

बिलासपुर जिले की पर्वतारोही सुश्री निशु सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। देश- विदेश की कई प्रमुख पर्वत चोटियां फतह कर चुकी सुश्री निशु ने 21 मई 2024 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के 26,200 फिट पर तिरंगा फहराया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा की आपकी इस शानदार उपलब्धि ने छत्तीसगढ़ को भी गौरवान्वित किया है। इससे उभरते पर्वतारोहियों को भी एक प्रेरणा मिलेगी। सुश्री निशु ने बताया कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान उन्हें कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बार बार खराब होते मौसम, बर्फबारी, कम होते ऑक्सीजन लेवल और ठंडी हवाओं ने उनकी कठिन परीक्षा ली, लेकिन उनके बुलंद हौसलों को डगमगा नहीं पाई। आखिरकार उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया और दृढ़ साहस और इच्छाशक्ति के बदौलत माउंट एवरेस्ट के 26,200 फिट पर तिरंगा फहरा दिया।

स्वास्थ्य विभाग में संविदा के विभिन्न पदों पर पुनः साक्षात्कार-कौशल परीक्षा

रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में संविदा आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती निकली गई थी। जिला चिकित्सालय में पहले आयोजित साक्षात्कार-कौशल परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया था। साक्षात्कार-कौशल परीक्षा विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग तिथियों में जिला चिकित्सालय के सभाकक्ष में सुबह 10 बजे से 22 जुलाई से 16 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट https://gaurela-pendra-marwahi.cg.gov.in पर देख सकते हैं। जिले में आर.ओ.पी. वर्ष 2022 से 2024 तक में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा आधार पर स्टाफ नर्स एनआरसी, नर्सिंग ऑफिसर एनएचएमपी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर साइकैट्रिक नर्स, साइकेट्रिक-क्लीनिकल, सेकेण्ड एएनएम, एएनएम आरबीएसके, डेंटल असिस्टेंट, फिजीयोथैरेपिस्ट, ब्लॉक सुपरवाइजर वीबीडी, एसटीएस, एमओ-आयुष, ओटी-टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट एवं नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती किया जाना है।

छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार 17 जुलाई को सुबह 11.30 बजे राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम(साइंस कालेज परिसर) में रखा गया है। शपथ ग्रहण समारोह सम्मानित अतिथि बृजमोहन अग्रवाल,सांसद रायपुर व पूर्व मंत्री,श्री अरूण साव,उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन,श्री विजय शर्मा,उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री अमर अग्रवाल,विधायक बिलासपुर व पूर्व मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में रखा गया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल सोनी,महासचिव प्रकाश गोलछा व कोषाध्यक्ष हर्षवर्धन जैन ने कहा है कि बस्तर से अंबिकापुर,रायगढ़ से राजनांदगांव विकास व विस्तार के लिए समर्पित हमारी कार्यकारिणी अपना कार्यक्षेत्र रायपुर व बिलासपुर तक ही सीमित रखना नहीं चाहती है,पूरे प्रदेश के सराफा कारोबारियों को जोडने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक प्रदेश ..सराफा व्यापार,सबका विश्वास..सबका साथ। हमारा एक परिवार ..छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन की भावना को लेकर पूरी पारदर्शिता के साथ कार्यकाल संचालित करने के लिए शपथ भी पहली बार हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील ओटवानी की मौजूदगी में लेने जा रहे हैं। पदाधिकारियों ने सभी सराफा कारोबारियों से परिवार सहित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आग्रह किया है।

वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन सोशल एक्टीविटी ग्रुप बैठक में तीज महोत्सव का निर्णय

रायपुर। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन छ.ग. सोशल एक्टीविटी ग्रुप की बैठक श्री जगन्नाथ मन्दिर परिसर, रायपुर में पुरंदर मिश्रा, श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्टी एवं विधायक रायपुर उत्तर के मुख्य आतिथ्य एवं श्री अरविन्द ओझा, प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अतिथि पुरन्दर मिश्रा का सभी सदस्यों ने पुष्पगुच्छ एवं शाल द्वारा सम्मान किया एवं भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द ओझा ने संगठन के आगामी कार्यक्रम सावन माह में भगवान शंकर का अभिषेक एवं महिलाओं हेतु तीज महोत्सव के आयोजन के विषय में सभी सदस्यों को अवगत कराया। महिला अध्यक्ष नमिता शर्मा ने तीज महोत्सव अवसर पर छत्तीसगढ़ स्तरीय महिलाओं की नृत्य प्रतियोगिता के विषय में विस्तार से बताते हुए सहभागिता की अपील की एवं सांस्कृतिक सचिव प्रीति मिश्रा नृत्य प्रतियोगिता के नियम व शर्तो की जानकारी प्रदान की। सभी की उपस्थित सदस्यों ने तीज महोत्सव कार्यक्रम की समय सारणी व संयोजक सह संयोजक चयन पर सहमति प्रदान की। इस बैठक विशेष रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुणानिधि मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव सुरेश मिश्रा, महासचिव सुनील ओझा, प्रांतीय सलाहकार रज्जन अग्निहोत्री सहित सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे।

उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार देगी हर संभव सहयोग : साय

नई औद्योगिक नीति 2024-29 के संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहयोग करेगी। नए उद्योगों की स्थापना हो, छत्तीसगढ़ में वैल्यू एडिशन का काम हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी सरकार की मंशा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उक्त बातें आज यहां अपने निवास कार्यालय में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई औद्योगिक नीति 2024-29 के लिए दिए गए सुझावों पर चर्चा के दौरान कही।

इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, सीआईआई के छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के चेयरमैन श्री आशीष सराफ, वाइस चेयरमैन श्री संजय जैन, सर्व श्री नरेंद्र गोयल, आनंद सिंघानिया, रमेश अग्रवाल, पंकज सारडा सहित सीआईआई छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने सिंगल विंडो सिस्टम और मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों और बहुमूल्य खनिजों के विपुल भंडार मौजूद हैं। प्रदेश में लघु वनोपजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि चाहे खनिज हो या लघु वनोपज, इनका वैल्यू एडिशन छत्तीसगढ़ में ही हो, ताकि प्रदेश को इसका लाभ मिले। श्री साय ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सैकड़ो एमओयू हुए हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। राज्य सरकार की मंशा है कि यहां नए-नए उद्योग स्थापित हों, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सीआईआई द्वारा नई औद्योगिक नीति के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, प्रदेश

के उद्योग मंत्री और नीति तैयार करने वाली समिति को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों का अध्ययन कर, अच्छे सुझावों को नई औद्योगिक नीति में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना की है और अगले 5 वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नई औद्योगिक नीति और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाएगा।

भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम की प्रशंसा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सिंगल विंडो सिस्टम के लिए एक टाइम फ्रेमवर्क का भी निर्धारण किया जाए। उन्होंने लघु वनोपज का वैल्यू एडिशन, डेयरी उद्योग, स्टील उद्योग में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की काफी संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ पॉवर सरप्लस स्टेट है इसलिए यहां डेटा सेंटर स्थापित किए जा सकते है क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग होता है। सदस्यों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नई औद्योगिक नीति में शामिल किया जाए। इस अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने नई औद्योगिक नीतियों पर आधारित अपने सुझावों का प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत किया।

महतारी वंदन : मंत्री चौधरी ने हकीकत जानने भूपेश को गांव आने का दिया न्योता

पूर्व मंत्री डहरिया बोले- कई महिलाओं को अब नहीं मिल रहा महतारी वंदन का पैसा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने गांव आने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा, 70 लाख माता बहनों को हर माह 1000 मिलने पर भूपेश बघेल के पेट में दर्द हो रहा है। उनके गांव में जाकर यदि हाथ खड़े कराएंगे तो कितनों का हाथ उठेगा। ये भूपेश बघेल खुद जाकर देख सकते हैं। वहीं महतारी वंदन योजना को लेकर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जिन लोगों को महतारी वंदन की राशि जारी रही थी उनकी सूची सरकार को जारी करनी चाहिए।

डहरिया ने कहा, पहले चुनाव के समय सभी लोगों से फॉर्म भरवाए गए। चुनाव के समय तक बहुत सारे लोगों को राशि दी गई। उसके बाद अब आधे से ज्यादा लोगों का नाम काट दिया गया। गांव-गांव में यह

शिकायत आ रही है कि पहले पैसा मिलता था अब नहीं मिल रहा है।

मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, कांग्रेस की सरकार बनने से पहले मैनिफेस्टो में महिलाओं को 500 हर महीने देने का वादा किया गया। पांच साल तक किसी को पांच रुपए तक नहीं दिए। हमारी सरकार में महिलाओं को 1000 प्रति महीने मिल रहा। पीएससी घोटाले की जांच पर वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस राज के दौरान पीएससी में माफिया राज चला। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि भर्तियों में गड़बड़ियां समाप्त हो। हमने सीबीआई जांच का वादा किया, जांच की जा रही है। कांग्रेस सरकार की तुलना में आने वाले पांच सालों में कई गुना ज़्यादा भर्तियां होंगी।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने 5 साल में मलेरिया को जड़ से उखड़ने की बात कही है। इस मामले में पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा, हमारी सरकार थी तो मलेरिया के उन्मूलन के लिए बड़ा काम हुआ था। अब लोग चिकित्सा के अभाव में मरते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। सुदूर अंचलों में कहीं पर डॉक्टर नहीं है दवाइयां नहीं है। यहां के सबसे बड़े अंबेडकर हॉस्पिटल में खून की जांच करने के लिए रीजेंट नहीं है। राजधानी में यह स्थिति है तो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति को आप समझ सकते हैं।

राजस्व पखवाड़ा को लेकर पूर्व मंत्री शिवकुमार डहेरिया ने कहा, बेकार है राजस्व पखवाड़ा। एक भी हितग्राही को कोई भी लाभ नहीं मिला। पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। गांव से मेरे पास जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र वाले बच्चे आए थे कि हमारे पत्र नहीं बन रहे हैं। उनका राजस्व पखवाड़ा पूरी तरीके से फेल है।

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को सरकार बंद करेगी, इस मामले में पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा, वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़ी संस्कृति खेलकूद का विरोधी है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में पूरे प्रदेश के लोग शामिल होते थे। इसे बंद करना निंदनीय है, नाम बदल दें पर बंद न करें।

देवार डेरा को हटाने लालपुर के लोगों ने किया चक्काजाम

रायपुर। राजधानी के लालपुर क्षेत्र से अवैध देवार डेरा बस्ती और शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने चक्काजाम किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध देवार डेरा बस्ती के लोग आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट करते है, जिससे राहगीर व स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर डेरा डालने वाले 40 से 50 परिवारों को बोरिया खुर्द में शिफ्ट कर रही।

लालपुर और कमल विहार के लोगों ने देवार डेरा के लोगों पर आए दिन मारपीट व लूटपाट करने का आरोप लगाया है। बीती रात स्थानीय लोगों से मारपीट की गई, जिसमें दो युवक घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में सीएसपी

राजेश देवांगन ने कहा, कुछ लोग यहां डेरा बनाकर रहे रहे थे, जिसे हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग चक्काजाम कर रहे थे। यहां डेरे वाले लोगों को यहां से हटाया जा रह है।

बोरिया खुर्द में उनके लिए जगह स्थापित की गई है। कई बार यहां पर सूचना मिल रही थी कि आने-जाने वाले लोगों के साथ मारपीट करते हैं। साथ ही कल ही एक घटना में तीन-चार लोग शामिल पाए गए है। इसके बाद यहां से लोगों को हटाया जा रहा है। 40 से 50 परिवार हैं, जिनको बोरिया खुर्द में आवास के मकानों में शिफ्ट किया जाएगा।

सेजबहार जनकल्याण समिति के कार्यों की होगी जांच

रायपुर। हाउसिंग बोर्ड कालोनी सेजबहार के रहवासियों ने सोमवार को शंकरनगर स्थित बोर्ड कार्यालय में उपायुक्त संदीप वर्मा से मिलकर सफाई और रखरखाव का काम कर रही सेजबाहर जन कल्याण समिति के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की।रहवासियों की शिकायत को उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए समिति के कार्यों की जांच कराने के साथ ही अनुबंध निरस्ती की कार्रवाई का आश्वासन दिया।

रहवासियों ने बताया कि 1366 स्वतंत्र मकानों वाले सेजबहार कालोनी के पांच हजार से अधिक रहवासी सालों से चारों तरफ पसरी गंदगी,नाली जाम,पेयजल संकट आदि की समस्या से परेशान है।बारिश में सफाई न होने के कारण जलजनित बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है।अगस्त 2020 से कालोनी के रखरखाव, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल आपूर्ति का काम विवादित जन कल्याण समिति को बोर्ड के अधिकारियों ने देकर रहवासियों को मुसिबत में डाल दिया है। समिति के पदाधिकारी केवल लोगों से पानी, सफाई के नाम पर पैसा वसूलने और बोर्ड की खाली पड़ी हुई जमीनों पर कब्जा करने का काम कर रहे है। चार साल बाद भी मात्र 44 लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया है और वे ही आपस में गुपचुप तरीके से पदाधिकारियों का चुनाव कर लेते है, जबकि नियमानुसार आबादी के अनुरूप 35 प्रतिशत सदस्य होने चाहिए। समिति ने आय-व्यय का लेखा-जोखा तक सार्वजनिक नहीं किया है। बोर्ड का नियम है कि समिति के कार्य की समीक्षा छह महीने में होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। कालोनी के रहवासी सुनील ठाकुर, धनेश दिवाकर, दीपक नायडू, राहुल ठाकुर, विजय गुप्ता आदि ने अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर समिति का अनुबंध तत्काल निरस्त कर उसके बैंक खातों की जांच करने के साथ ही नए सिरे से समिति का चुनाव बोर्ड के अधिकारियों की निगरानी में कराने की मांग की है।

महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर बने विशेष रणनीति

रायपुर। नीति आयोग द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में महिलाओं ने विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पर विचार रखते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं को सशक्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पर विशेष रणनीति बनानी होगी। महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से जोड़कर आर्थिक गतिविधियों के लिए तैयार करना होगा। कार्यक्रम में महिलाओं ने इस बात पर जोर दिया कि लैंगिक भेदभाव, नशाखोरी, बाल विवाह सहित सभी सामाजिक बुराईयों के प्रति जनजागरण अभियान भी चलाने की आवश्यकता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने, उनके कौशल विकास, नये स्टार्टअप शुरू करने के लिए नये कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है। कार्यक्रम में शताब्दी पाण्डेय ने कहा कि सहकारिता से जुड़कर ही महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। इसके लिए राज्यस्तरीय, अंतर्राज्यीय और देशव्यापी संस्थाओं और बहुस्तरीय सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्रीमती शमशाद बेगम ने कहा कि सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए ठोस पहल होनी चाहिए। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के रूप में पहचान रखने वाली श्रीमती लामी बैगा, पुष्पा वस्त्रकार और चित्ररेखा साहू ने कहा कि उद्यमिता से जुड़े महिलाओं के लिये मार्केटिंग, पैकेजिंग और विक्रय की व्यवस्था करना जरूरी है।

■ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने सहकारिता से जोड़ने की जरूरत

मुख्यमंत्री साय की संवेदनशीलता से तीन को मिली अनुकंपा नियुक्ति

शारदा, प्रमिला, एवं अन्नपूर्णा बनेंगी अपने परिवार का सहारा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सरकार लोगों के हित में त्वरित कार्य कर रही है। समय सीमा के अंदर जरूरतमंद परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकें, शासन इस पर लगातार प्रयास कर रही है। गरियाबंद जिले की श्रीमती शारदा पटेल, श्रीमती प्रमिला कुर्रे एवं सुश्री अन्नपूर्णा ध्रुव को अनुकम्पा नियुक्ति मिल गई है। कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल ने तीनों को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किया। शासन की त्वरित कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

ग्राम देवरी जिला जांजगीर चांपा की रहने वाली श्रीमती शारदा पटेल ने बताया कि उनके पति व्याख्याता के रूप में हायर सेकेण्डरी स्कूल अकलवारा में पदस्थ थे। उनके निधन के बाद भृत्य पद के रूप में अनुकंपा नियुक्ति शासकीय हाईस्कूल लोहझर में मिली है। उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति मिलने से परिवार के पालन पोषण एवं देखरेख में सहायता मिलेगी। साथ ही भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार मचेवा जिला महासमुंद की रहने वाली श्रीमती प्रमिला कुर्रे के पति शिक्षक (एलबी) के रूप में शासकीय

मीडिल स्कूल गुड़ेमा में पदस्थ थे। उनके निधन के पश्चात उन्हें भृत्य के रूप में शासकीय हाईस्कूल सेमरा में अनुकंपा नियुक्ति मिली। उन्होंने बताया कि पति के जाने के बाद भविष्य चिंतित था।

छत्तीसगढ़ शासन की पहल से अनुकंपा नियुक्ति मिलने से बच्चों के पढ़ाई -लिखाई एवं भविष्य सृजन में मदद होगी। मैनपुर अंतर्गत ग्राम गोना के निवासी सुश्री अन्नपूर्णा ध्रुव के पिता शासकीय मीडिल स्कूल गरहाडीह में शिक्षक (एलबी) के पद पर पदस्थ थे। उनके निधन के पश्चात राज्य शासन की संवदेनशीलता के कारण त्वरित रूप से अन्नपूर्णा को भृत्य पद में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल शोभा में अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक बंद करने पर भाजपा नेता अजय चंद्राकर का बड़ा बयान

कहा- विधानसभा सत्र के दौरान सामने आएंगे नए तथ्य, छत्तीसगढ़ ओलंपिक और राजीव युवा मितान क्लब का पैसा एक ही जगह हुआ खर्च

रायपुर। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बंद करने पर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि (विधानसभा) सत्र शुरू होगा, तो देखिएगा नए तथ्य सामने आएंगे। जब तक हम इसे परिणाम तक नहीं ले जाएंगे, तब तक सवाल लगते रहेंगे। जो कन्वर्जेंस हुआ हैं, जिसमें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का पैसा और राजीव युवा मितान क्लब का पैसा एक ही जगह खर्च हुआ है। दोनों के पैसों का हिसाब-किताब क्या है, ये जब तक साबित नहीं होगा, चलता रहेगा।

वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने इसके साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई द्वारा शुरू किए जाने पर कहा कि कांग्रेस का मापदंड नीट के मामले में अलग हैं, और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मामले पर अलग है। मोदी जी की गारंटी थी कि हम जाँच करायेंगे। जांच शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को न्याय

मिलेगा।

कुरुद विधायक ने कहा कि परीक्षा लेने वाली संस्थाओं और परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था। नीट का मामला हो या पीएससी की, दोनों वक्त कांग्रेस का शासन था। मोदी जी की गारंटी थी, जाँच शुरू हुई। बेरोज़गारों को, योग्य प्रतियोगियों को अवसर मिले।

वहीं सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फालोअर्स की संख्या सौ मिलियन पार करने को कांग्रेस के पैसे के बल पर बताए जाने पर अजय चंद्राकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के ही नहीं, विश्व के नेता हैं। उनका कद कांग्रेस को कभी स्वीकार ही नहीं हुआ। कांग्रेस के एक परिवार के तीन लोगों को छोड़कर किसी का कद स्वीकार नहीं कर सकती। तीन लोगों के अलावा दुनिया में क्या घट रहा है, इससे कांग्रेस को मतलब नहीं। एक परिवार के बाहर कांग्रेसी सोचते नहीं हैं।

कांग्रेस ने मानसून सत्र बढ़ाने की मांग पर अजय चंद्राकर ने कहा कि चरणदास महंत को सोचना चाहिए। भूपेश बघेल ने कितने दिनों का सत्र बुलाया था। विधानसभा अध्यक्ष थे तो उनको भूमिका क्या थी? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसके लिये खुद दोषी हों। सबसे छोटा सत्र बुलाने का श्रेय अजीत जोगी और भूपेश बघेल के पास है। परंपराओं को इन लोगों ने दूषित किया है, इसीलिए उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के सर्वे कराए जाने पर अजय चंद्राकर ने कहा कि इनका सर्वे है गांधी के परिवार के इच्छाओं का पालन करना। वो जो बोल दें, वही सर्वे है। किस बात का सर्वे करवाएंगे। उम्मीदवार नहीं मिल रहा। जीतने की संभावना या लड़ेंगे की नहीं इस बात की सर्वे कराएंगे? कांग्रेस में कितने गुट हैं, उसको कैसे समाप्त करें, इसका सर्वे कराएंगे। सर्वे के मुद्दे क्या हैं इसे बताए, कांग्रेस के सर्वे में दम नहीं है।

कांग्रेस में भूपेश गुट के जिला अध्यक्षों को बदलने की तैयारी भाजपा विधायक ने कहा कि भूपेश गुट के लोग हटेंगे, तो दूसरे गुट के लोग बन जाएंगे। वहीं कांग्रेस के विधानसभा के घेराव पर अजय चंद्राकर ने कहा कि शौक से घेरना चाहिए। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जिंदा होना नहीं, जिंदा हैं, ये बताने के लिए उनको कदमताल करना चाहिए। ट्वीट-ट्वीट करने की बजाए कुछ आगे बढ़ें। भूपेश बघेल को जिंदा दिखने के लिए बधाई।

व्यापमं ने जारी किया एडमिट कार्ड

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने राज्य पात्रता परीक्षा (सीजी सेट) का एडमिट कार्ड कर दिया है। विभाग के आधिकारिक वेबसाइट अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन 21 जुलाई को होगी। इसके लिए राज्य के कई जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यह परीक्षा सुबह साढ़े नौ से साढ़े 12 बजे तक और दोपहर दो से शाम पांच बजे तक होगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, अटल नगर, रायपुर, (छ.ग.)

ज्ञाप क्रमांक/प्र.अ./T/4943002/2024-25 पर्य — अटल नगर दिनांक 12/07/2024

// भाव पत्र आमंत्रण सूचना //

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, सेक्टर-19 नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, के लिए वर्ष 2023-24 में कार्यालय लेखन स्टेशनरी सामग्री प्रदाय करने की दर दिनांक 25.07.2024 तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भाव पत्र आमंत्रित किये जाते है।

कार्यों की जानकारी कार्यालयीन दिवस में कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, सेक्टर-19 नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 22.07.2024 तक प्राप्त की जा सकती हैं।

अधीक्षण अभियंता
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

जी-242501090/4

संसदीय संवाद की परंपरा को बहाल रखा जाए

कौशल किशोर

नया संसद भवन नई लोकसभा के पहले दिन से ही विपक्ष के नेता से सुसज्जित होने लगा। इसका अभाव एक दशक तक देश ने झेला है। गांधीवादी सफेद खादी की धज में सजे राहुल गांधी नेहरू-गांधी परिवार की परंपरा की याद दिलाते हैं। फोटो शूट के पहले शालीन सत्र के बाद धुआंधार पारी की शुरुआत करते प्रतीत हुए। उनके मुरीद अहलादित हैं। सामने वाले को मूर्छित मान कर खूब प्रसन्न भी। हालांकि उनके इस वक्तव्य के 13 टुकड़ों को संसदीय कार्यवाही से निकाल दिया गया है। उन्होंने लोक सभा अध्यक्ष को खत लिख कर इसका प्रतिकार किया। इस पर प्रैस कांफ्रैंस कर इन टुकड़ों को सांझा करने की चुनौती भी उनके सामने पेश है। लेकिन अगले ही दिन राहुल सामान्य परिधान और विवादास्पद मुद्दों की श्रृंखला के साथ अपने मूल स्वरूप में लौट आए। उन्होंने जेल में बंद अपने एक सहयोगी का नाम लिए बगैर जिक्र भी किया। आज राहुल गांधी लोक पाल और सी.बी.आई. निदेशक ही नहीं बल्कि चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त और सतर्कता आयुक्त जैसे अहम पदों पर नियुक्ति करने वाले पैनल के सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। ऐसा लगता है कि सत्ता से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। अगले पांच वर्ष तक एक डग बढ़ना आसान नहीं है। सत्ता को 2013 से ही जहर बताने वाले राहुल गांधी पिछले साल कश्मीर पहुंच कर सूफी हो गए थे। केंद्र सरकार की लेखापरीक्षा व व्यय समिति में शामिल होकर उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सरकार के औपचारिक शिष्टाचार में उन्हें 7वां स्थान प्राप्त हो गया है। साथ ही उन्हें नई संसद में कर्मचारियों और सुविधाओं से युक्त एक सुसज्जित कार्यालय भी मिला है। विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें बहस शुरू करने और प्रधानमंत्री के भाषण का जवाब देने का विशेषाधिकार भी प्राप्त हो गया है। उनके पिता और माता दोनों ही देश के शीर्ष सार्वजनिक कार्यालय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चलाने से पहले इसी पद पर आसीन थे। उनके पहले संबोधन का असर जनता और मीडिया में साफ तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और विभिन्न दलों के अन्य सांसदों को मजबूती से खड़े होकर अपनी चिंताओं को उठाने के लिए मजबूर किया। उनके भाषण से असंसदीय संदर्भ लोक सभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिए गए। लेकिन अभी भी यह संसद टी.वी. और कई अन्य मीडिया चैनल के रिकार्ड में मौजूद है। उन्होंने भगवान शिव के अहिंसक त्रिशूल को परिभाषित किया। गुरु नानक देव जी, ईसा मसीह आदि की अभय मुद्रा का उल्लेख कर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ से इनकी तुलना कर दी। उन्होंने कहा, शिवजी कहते हैं कि डरो मत और दूसरों को डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं। अहिंसा की बात करते हैं और अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ देते हैं। जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, वे 24 घंटे हिंसा, नफरत और झूठ की बात करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं की ओर से इसका जवाब दिया। फिर राहुल गांधी ने कहा, ''आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि आपको सत्य का साथ देना चाहिए और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्य से डरना नहीं चाहिए और अहिंसा हमारा प्रतीक है।''अहिंसक त्रिशूल और निर्भयता के इस विचार को 1909 में दशहरा के दिन लंदन स्थित इंडिया हाऊस में रामायण व महाभारत के संदर्भ में सावरकर और गांधी द्वारा शुरू की गई बहस का विस्तार माना जा सकता है। इसी दोहन की प्रक्रिया में अयोध्या मक्खन की तरह उभरता है। उसी वर्ष लंदन से लौटते समय यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ब्रिटिश संसद को वेश्या के रूप में परिभाषित करते हैं। उन्होंने सत्याग्रह ब्रिगेड की महिला पार्टी को खुश करने के लिए अपनी पुस्तक 'हिंद स्वराज' के संशोधित संस्करण में इसे संपादित किया था। लेकिन वेश्यालय के उनके संदर्भ को जानने के लिए इसके पीछे की कहानी समझने की जरूरत है।

संविधान हत्या दिवस में राजनीतिक प्राणतत्व कितना?

अजय बोकिल

देश में हालिया लोकसभा चुनाव और उसके बाद भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने भाजपा को संविधान बदलने के मुद्दे पर जिस तरह से घेरा है, मोदी सरकार द्वारा 25 जून को हर साल 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने की अधिसूचना बेशक तगड़ा और तात्कालिक राजनीतिक पलटवार तो है, लेकिन इससे भाजपा को कोई बड़ा दीर्घकालीन सियासी मिल सकेगा, इसमें संदेह है। इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य संविधान बदलने के सवाल पर उस कांग्रेस पर ही ठीकरा फोड़ना है, जिसे भाजपा अब 'सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली' की तर्ज पर कटघरे में खड़ा करना चाह रही है।

भाजपा का कहना है कि खुद कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कई बार संवैधानिक मर्यादाओं को भंग किया, लोकतंत्र को कुचला, ऐसे में उसे भाजपा की नीयत पर उंगली उठाने का कोई नैतिक हक नहीं है। यानी कि वह भाजपा को घेरने की जगह पहले अपने गिरेबान में झांके। हमने तो घोषित तौर वैसा कुछ भी नहीं किया है, जो कांग्रेस ने डंके की चोट पर किया। बावजूद इसके बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस इस मुद्दे पर कहीं से भी रक्षात्मक नजर नहीं आ रही है।

वह अपने इस आरोप को बेखौफ दोहरा रही है कि संविधान के मामले में भाजपा का रवैया 'मुंह में राम बगल में छुरी' वाला है। मौका देखकर वह वही करेगी, जिसकी आशंका लोगों के मन में है। आशय यह कि भाजपा देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इसकी टेस्टिंग वह जब तब करती रहती है। हाल में दिल्ली विवि में कानून की पढ़ाई में मनुस्मृति को शामिल करने का दांव और फिर इसके राजनीतिक खतरे को भांपने के बाद फैसले की वापसी इसी आशंका के स्पष्ट लक्षण हैं।

भाजपा नेता इसे खारिज तो करते हैं, पर उसमें उतना विश्वास नहीं झलकता। संविधान और आरक्षण का मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिसे चलताऊ ढंग से हैंडल किया जाए। अगर भाजपा के हाथ से दलित और कुछ ओबीसी वोट बैंक यूं ही खसकता गया तो यूपी में अगला विधानसभा चुनाव जीतना भी उसके लिए टेढ़ी खीर होगा। लोकसभा चुनाव में उप्र में पार्टी की करार हार के कारणों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कर उसके समाधान के उपाय खोजने की बजाए

जिस तरह योगी आला कमान को और उप मुख्यमंत्री सीएम योगी पर हमला कर रहे हैं, उससे साफ है कि यूपी में भाजपा के हालात डेढ़ दशक पुरानी स्थिति में लौट रहे हैं।

वैसे संविधान को बचाने और बदलने का यह खेल कुल मिलाकर धारणा का खेल ज्यादा है, जिसमें भाजपा कांग्रेस को पटखनी देना चाहती है, लेकिन सही दांव लग नहीं रहा। यहां कांग्रेस के साथ सुविधा यह है कि वह केन्द्र में विपक्ष में बैठी है, इसलिए जवाबदेही के कॉलम को वह खाली भी छोड़ दे तो खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाजपा और एनडीए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह सत्ता में हैं।

यह बात साफ है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए को जिन तीन राज्यों यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उसके पीछे कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों द्वारा बनाया गया यह नरेटिव प्रमुख था कि मोदी और भाजपा के 400 के पार के अतिआत्मविश्वासी नारे का असल मकसद संविधान बदलना है और इसे बदलने का मतलब देश में ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के संविधान प्रदत्त आरक्षण को खत्म करना है। परोक्ष रूप से उस राज को वापस लाना है, जिसमे अगड़ी जातियों का ही वर्चस्व रहेगा। दूसरे शब्दों में यह 'ब्राह्मणवाद' की पुनर्स्थापना की कोशिश होगी।

हालांकि, घोषित तौर पर किसी भाजपा नेता ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन संविधान बदलने की सुर्री छोड़कर अपनी ही पार्टी के मैदान में सेल्फ गोल जरूर किया। जबकि कांग्रेस ने 'बिटवीन द लाइंस' पर ही चुनाव का ऐसा तगड़ा नरेटिव खड़ा किया, जिसे चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कुछ राज्यों में धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण खत्म करने के नरेटिव में बदलने की असफल कोशिश की। असफल इसलिए कि हाल के विधानसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ टीडीपी ने राज्य में मुसलमानों को धर्म के आधार पर 4 फीसदी आरक्षण जारी रखने का ऐलान किया। लेकिन भाजपा अब चुप है, क्योंकि वह भी राज्य में सत्ता में भागीदार है।

ऐसा लगता है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा हर सभा में संविधान की प्रति लहराकर भाषण देने और लोकसभा में भी शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस सांसदों दवारा संविधान की प्रतियां दिखाने से परेशान भाजपा और मोदी ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए संविधान हत्या दिवस' का कड़वा डोज देने की कोशिश की है। लेकिन यहां सवाल सियासी पलटवार से ज्यादा उसकी राजनीतिक उपादेयता का है। बेशक आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित हुए। इंदिरा सरकार ने सभी विरोधियों को जेल में डाला। कई घरों में चूल्हा बुझने की नौबत आई। कुछ की जानें भी गईं। लोकतंत्र मूक हुआ। भाजपा चाहती है कि लोग कांग्रेस के उन संविधान विरोधी और लोकतंत्र को कुचलने के कारनामों को याद करें।

उसका असली चेहरा जानें। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस भाजपा के इस वार को पाखंड कहकर खारिज कर दिया है। यह भी सच है कि आपातकाल और उसकी आगे के राजनीतिक घटनाक्रम ने ही आरएसएस की राजनीतिक शाखा जनसंघ को भाजपा में तब्दील होने का स्वर्णिम अवसर भी दिया, जो आज सत्ता में है। कहना मुश्किल है कि अगर आपातकाल न लगता तो जनसंघ अपनी राजनीतिक यात्रा के कितने पड़ाव पूरे कर पाता और क्या भाजपा कभी वजूद में आती?

जहां तक कांग्रेस की बात है तो हाल में 12 सीटों पर हुए विस उपचुनाव के नतीजों ने उसकी हौसला अफजाई ही की है। हमे यह भी याद रखना होगा कि जनता और अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते इंदिराजी ने आपातकाल लगाने के 19 माह बाद इंदिराजी ने ही देश में चुनाव भी करवाए और सभी बंदियों को छोड़ा। जनता ने उन्हें चुनाव में पराजित कर 'लोकतंत्र की हत्या' के लिए सजा भी दे दी। इन सबके बाद भी वह 25 साल तक अकेले अथवा गठबंधन के रूप में सत्ता में रही।

देश में इमरजेंसी को लागू हुए अब पचास साल हो रहे हैं। आज राजनेताओं की सक्रिय पीढ़ी में से अधिकांश ने सिर्फ आपातकाल की कहानियां सुनी हैं। जब आपातकाल लगा और हटा था तब इनमें से ज्यादातर स्कूल के विद्यार्थी रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने इमरजेंसी को देखा और भुगता, वो अब ज्यादातर मार्गदर्शक की श्रेणी में हैं। ऐसे में नई पीढ़ी को आपातकाल के 'अत्याचारों' के बारे में बताने का कोई बहुत व्यावहारिक लाभ होगा, इसकी संभावना न्यून है।

यह बहुत कुछ वैसा ही है कि कांग्रेस आजादी के बाद कई सालों तक इसी की राजनीतिक कमाई खाती रही कि आजादी की लड़ाई उसीने लड़ी, देश के लिए कुर्बानियां दीं। लिहाजा सत्ता में बने रहने का उसका नैसर्गिक अधिकार है। लेकिन हकीकत में आजादी के तीस साल पूरे होने तक जनता की निगाह में कुर्बानियों और अंग्रेजी अत्याचारों की उन कहानियों की मार्मिकता और बलिदानों की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगी थी।

इसी का परिणाम आगे चलकर एक अलग वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़ी भाजपा के उत्थान में हुआ। ऐसे में भाजपा का संविधान हत्या दिवस' उसी पुराने नुस्खे को नए पैकिंग में चलाने की कोशिश ज्यादा लगती है। इसमें कितना वास्तव में राजनीतिक प्राणतत्व है, इसकी परीक्षा देश में तीन माह बाद चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव नतीजों में हो जाएगी। भाजपा के सामने असली चुनौती यही है कि अगर यह दांव नहीं चला तो वह अपनी प्रांसगिकता बनाए रखने के लिए कौन सी रणनीति अपनाए? केन्द्र में भाजपा के बजाए एनडीए सरकार बनने के बाद राज्यसभा में सीटें और घटना उसके लिए नई मुश्किल खड़ी करेगा।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

उप-पुराण (भाग-4)

गतांक से आगे...

यह पुराण वास्तव में एक लक्ष श्लोक संख्या वाला द्वादशसंहितात्मक: बृहद् ग्रन्थ था जो साक्षात् शिव भगवान् द्वारा हो उपदिष्ट हुआ था। इसके 76 हजार पद्य तो शिवलोक में प्रसिद्ध हुबे शेष 24 हजार प्रमाण वाला अंश वायु ने भूलोक में प्रचलित किया। इसलिए इस पुराण के दो नाम पड़ गये। जैसा कि निम्नलिखित प्रमाणों से जाना जाता है:-

(क) साक्षात् शिव के समान शिवपुराण वायु ने कथन किया है, वही शिवभक्ति का विधायक होने के कारण शिव पुराण तथा वायु पुराण इन दो दो नामों से विख्यात है। (ख) वेद सम्मत शिवपुराण शिव भगवान् का निर्माण किया हुआ है। (ग) जो एक लक्ष श्लोक प्रमाण वाला था, पश्चाद् व्यास जी ने 24 हजार प्रमाण में उसे संक्षिप्त किया।

अठारह पुराणों में भागवत नामक पुराण के स्थान में दो ग्रन्थ गिने जाते हैं। एक श्रीमद्भागवत और दूसरा देवी-भागवत। छिद्रान्वेषी महाशय इन दोनों ग्रन्थों को जुदा जुदा गिन कर पुराण संख्या को 16 बनाने का प्रयास किया करते हैं। अथवा दोनों में किसी एक को पुराण मान कर दूसरे को उपपुराण कोटि में प्रविष्ट करना चाहा करते हैं। तथा वैष्णव और शाक्त सम्प्रदाय के लोगों द्वारा अपने अपने पुराण को उच्च कोटि में गिनाये जाने की चेष्टा के स्वप्न देखा करते हैं।

हमें इन बेचारे अदूरदर्शी नरपुंगवों की विवेचना बुद्धि पर दया आती है कि इन्हें संस्कृत साहित्य के साधारण से नियमों का भी रत्ती भर ज्ञान नहीं है। पुराण गणना में केवल भागवत नाम ही दिया गया है, कहीं भी श्रीमद् या देवी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अत: त्यक्तानुबन्धे सामान्यग्रहणम इस नियम के अनुसार भागवतत्व सामान्येन दोनों का ही ग्रहण होगा। भागवत शब्द की व्युत्पत्ति भी भगवतो भगवत्या वा इदम् भागवतम- इस प्रकार दोनों पुराणों के एकत्व में प्रमाण है।

क्रमश: ...

अखिल विद्यार्थी परिषद के आधार स्तंभ थे बाल आपटे

डॉ. राकेश मिश्रा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन में रीढ़ की भूमिका निभाने वाले बलवंत परशुराम (बाल) आपटे का जन्म 18 जनवरी, 1939 को पुणे के पास क्रांतिवीर राजगुरु के जन्म से धन्य होने वाले राजगुरुनगर में हुआ था। उनके पिता श्री परशुराम आपटे एक स्वाधीनता सेनानी तथा समाजसेवी थे। वहां पर ग्राम पंचायत, सहकारी बैंक आदि उनके प्रयास से ही प्रारम्भ हुए। यह गुण उनके पुत्र बलवंत में भी आये। बालपन से ही संघ के स्वयंसेवक रहे बलवंत आपटे प्रारम्भिक शिक्षा गांव में पूरी कर उच्च शिक्षा के लिए मुंबई आये और एल.एल.एम कर मुंबई के विधि महाविद्यालय में ही प्राध्यापक हो गये।

1960 के दशक में विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद लगभग 40 वर्ष तक उन्होंने यशवंतराव केलकर के साथ परिषद को दृढ़ संगठनात्मक और वैचारिक आधार दिया। विद्यार्थी परिषद ने न केवल अपने, अपितु संघ परिवार की कई बड़ी संस्थाओं तथा संगठनों के लिए भी कार्यकर्ता तैयार किये हैं। इसमें आपटे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

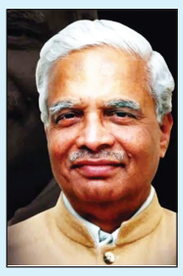

1974 में विद्यार्थी परिषद के रजत जयंती वर्ष में वे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गये। इस समय महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश में युवा शक्ति सड़कों पर उतर रही थी। इस आंदोलन को विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रव्यापी बनाया। जयप्रकाश नारायण द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने से यह आंदोलन और अधिक शक्तिशाली हो गया। इससे बौखलाकर इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। आपटे जी भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन करने लगे। दिसम्बर 1975 में वे पकड़े गये और मीसा नामक काले कानून के अन्तर्गत जेल में ठूंस दिये गये, जहां से फिर 1977 में चुनाव की घोषणा के बाद ही वे बाहर आये। जेल जीवन के कारण उनकी नौकरी छूट गयी। अत: वे वकालत करने लगे। अगले 20 साल तक वे गृहस्थ जीवन, वकालत और विद्यार्थी परिषद के काम में संतुलन बनाकर चलते रहे। उन्होंने संगठन के बारे में केवल भाषण नहीं दिये। वे इसके जीवंत स्वरूप थे।

उनकी एकमात्र पुत्री चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई पूरी कर दो वर्ष विद्यार्थी परिषद की पूर्णकालिक रही। फिर उसका अन्तरजातीय विवाह परिषद के एक कार्यकर्ता से ही हुआ। इस प्रकार विचार, व्यवहार और परिवार, तीनों स्तर पर वे संगठन से एक रूप हुए। 1996 से 98 तक वे महाराष्ट्र शासन के अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे। जब उन्हें भाजपा में जिम्मेदारी देकर राज्यसभा में भेजने की चर्चा चली, तो उन्होंने पहले संघ के वरिष्ठजनों से बात करने को कहा। इसके बाद वे आठ वर्ष तक भाजपा के उपाध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के सदस्य तथा 12 वर्ष तक महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य रहे।

नियमित आसन, प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान के बल पर आपटे जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था; पर जीवन में अंतिम एक-दो वर्ष में वे अचानक कई रोगों से एक साथ घिर गये, जिसमें श्वांस रोग प्रमुख था। समुचित इलाज के बाद भी 17 जुलाई, 2012 को उनका मुंबई में ही देहांत हुआ।

अमेरिका को नाटो के राह का रोड़ा नहीं बनना चाहिए

ज्योति भास्कर

अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति और नाटो के तहत यूरोप में मित्र देशों की अभियान सेना के पहले सर्वोच्च कमांडर जनरल ड्वाइट आइजनहावर का दृढ़ विश्वास था कि उनका मिशन यूरोपीय लोगों को अपनी सैन्य ताकत के बल पर खड़ा करना था, न कि अमेरिकी सैनिकों को ब्रूसेल्स एवं बर्लिन का स्थायी अंगरक्षक बनाना।

वर्ष 1951 में उन्होंने नाटो के बारे में लिखा था, यदि दस वर्षों में राष्ट्रीय रक्षा उद्देश्यों के लिए यूरोप में तैनात सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस नहीं भेजा गया, तो यह पूरी परियोजना विफल हो जाएगी। लेकिन विगत नौ जुलाई को जब नाटो सहयोगी देशों के नेता उसकी 75वीं वर्षगांठ के लिए वाशिंगटन में?सम्मिलित हुए, उस समय भी जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अन्य स्थानों पर लगभग 90 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो पांच लाख सैनिकों वाले नाटो के सैन्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाटो में अमेरिका की व्यापक मौजूदगी सिर्फ सैनिकों की बड़ी संख्या के कारण नहीं है, बल्कि यूक्रेन सपोर्ट ट्रैकर डाटाबेस के मुताबिक, दुनिया भर के देशों द्वारा यूक्रेन को आवंटित 206 अरब डॉलर की सैन्य व असैन्य सहायता राशि में से 79 अरब डॉलर की सहायता अकेले अमेरिका ने दी है। कैटो इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, 1960 के बाद से मित्र देशों के सकल घरेलू उत्पाद में अमेरिका की हिस्सेदारी औसतन लगभग 36 प्रतिशत रही है, जबकि मित्र देशों के सैन्य खर्च में इसकी हिस्सेदारी 61 प्रतिशत से अधिक रही है।

लेकिन, अब यह स्पष्ट है कि यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का अलगाववादी धड़ा इस बिंदु पर अमीर यूरोपीय देशों को आड़े हाथ लेते हैं कि ये देश सामाजिक सुरक्षा पर अमेरिका से भी ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इनके पास अपनी सेना के लिए पैसे

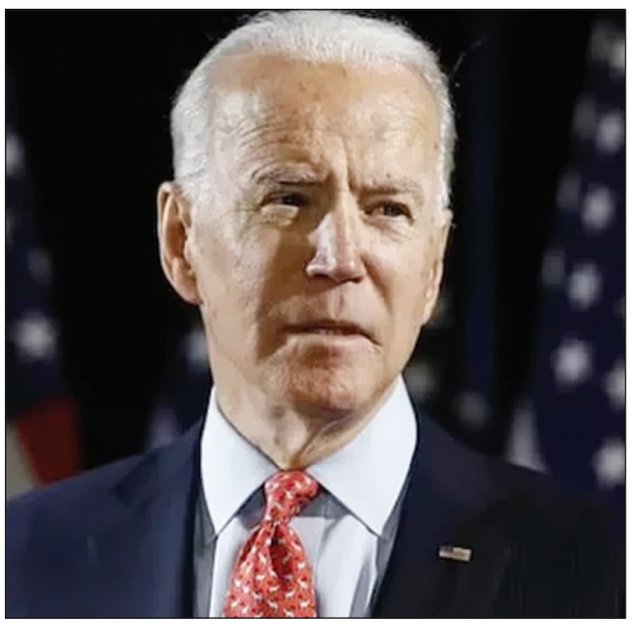

नहीं हैं। बल्कि, इसलिए भी कि अमेरिकी अधिकारी अब चीन द्वारा पेश की गई चुनौतियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए आने वाले वर्षों में अधिक संसाधनों की जरूरत होगी, खासकर चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के बढ़ते सहयोग को देखते हुए। अमेरिका हर जगह एक साथ, अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे ने बताया कि अमेरिकी चुनाव में चाहे जो भी जीते, यूरोपीय नेता समझते हैं कि उन्हें और अधिक योगदान देने की आवश्यकता है। वाशिंगटन की अपनी हालिया यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन नेतृत्व ने बताया कि यूरोपीय लोगों को यूक्रेन में युद्ध के लिए बहुत अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अमेरिका के पास और भी बड़े काम हैं।

इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं, जितनी होनी चाहिए। नाटो शिखर सम्मेलन की निस्संदेह यह उपलब्धि रही कि 23 नाटो सदस्यों ने अपने जीडीपी का कम से कम दो फीसदी अपनी सेना पर खर्च करने पर कुछ हद तक सहमति जताई, जबकि एक दशक पहले तक मात्र तीन सदस्य ही इतना खर्च करते थे। लेकिन आश्चर्यजनक है कि नाटो के 32 सदस्यों में से एक तिहाई अब भी खर्च के उस लक्ष्य से पीछे हैं, जिस पर 2014 में सहमति बनी थी। अगर रूस ने पूर्ण पैमाने पर हमला किया और नाटो सदस्य और खर्च करने के लिए राजी नहीं हुए, तो यह कल्पना करना मुश्किल है कि क्या होगा।

इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल अफेअर्स के ताजा सर्वे के मुताबिक, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एवं जर्मनी में अधिकांश लोगों का मानना है कि यूरोप को नाटो में बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी रक्षा के लिए प्रमुख जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अमेरिका पर यूरोप की निर्भरता महाद्वीप में बढ़ती बेचैनी को जन्म दे रही है। दरअसल, इसका एक कारण मानवीय स्वभाव है। अगर उनकी रक्षा के लिए हमेशा अमेरिका खर्च वहन करता है, तो सहयोगी क्यों निवेश करेंगे? लेकिन दूसरा कारण संरचनात्मक है। जब नाटो का गठन हुआ था, तो यूरोपीय सहयोगी विनाशकारी युद्ध से उबर ही रहे थे, जिससे वे एक दूसरे से संदेह करते थे और शत्रुतापूर्ण भी बन गए थे। ऐसे में कोई तो चाहिए था, जो उन सबको इकट्ठा करता। इस तरह, नाटो में अमेरिका की भूमिका अस्थायी सहायक से स्थायी रक्षक में बदल गई। लेकिन 1960 के दशक तक यह साफ हो गया कि अमेरिकी सेना जल्दी वापस नहीं जाएगी। एक बार जब वाशिंगटन को एहसास हो गया कि वह वहां से निकल नहीं सकता, तो उसने फैसले लेने शुरू कर दिए। पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के सुरक्षा सलाहकार मैकजॉर्ज बंडी ने 1962 में कहा, %हमें नेतृत्व की कीमत चुकानी होगी। इसके बदले हमें कुछ फायदे हो सकते हैं।%

इसका मतलब अमेरिकी फर्मों के लिए आकर्षक रक्षा अनुबंध थे, जो यूरोप में अपनी बड़ी उपस्थिति बनाए रखने के लिए शक्तिशाली वित्तीय प्रोत्साहन बन गए। अमेरिकी सैन्य उद्योग यूरोप की निर्भरता से लाभ कमाता है। वर्ष 2022-23 में यूरोपीय संघ के देशों द्वारा खरीदे गए सैन्य उपकरणों का लगभग 63 प्रतिशत अमेरिका से आया था। शीत युद्ध के अंत में यूरोपीय लोगों ने खुद को अमेरिकी सैन्य शक्ति से दूर करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नतीजतन आज यूरोप में नाटो के सदस्यों की रक्षा के लिए आवश्यक सैनिकों और उपकरणों को तैनात करने की क्षमता का अभाव है, खासकर जब बात वायु रक्षा, खुफिया और निगरानी जैसी विशेष इकाइयों की हो। सौभाग्य से कुछ यूरोपीय नेता इस मामले को उतनी ही तत्परता से ले रहे हैं, जितने की जरूरत है।

नाटो की खरीद योजना अमेरिकी हथियार निर्माताओं पर निर्भर है, जो यूरोपीय आयोग द्वारा मार्च में शुरू की गई नई यूरोपीय रक्षा औद्योगिक रणनीति के खिलाफ है। एक बार फिर, यूरोपीय देशों को एकजुट करने की जरूरत है। दोनों संस्थानों को एक मत होने की सख्त जरूरत है। अगर वे ऐसा करते हैं, तो यह यूरोप की अपनी रक्षा में मदद करने की क्षमता निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अतीत में अमेरिकियों ने खतरा महसूस कर यूरोपीय रक्षा उद्योग के निर्माण के प्रयास को विफल कर दिया होगा। लेकिन आज अमेरिकी खुद अपने औद्योगिक रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए जूझ रहे हैं। जैसा कि जनरल आइजनहावर ने सपना देखा था, आज यूरोपीय लोग अपनी रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, तो अमेरिका को राह का रोड़ा नहीं बनना चाहिए।

आज का इतिहास

1950 दक्षिण अफ्रीका में साम्यवाद अधिनियम लागू किया गया।
1968 अहमद हसन अल-बक्र द्वारा निर्मित, अरब सोशलिस्टबाथ पार्टी ने इराकी राष्ट्रपति अब्दुल रहमान आरिफ को उखाड़ फेंका।
1973 अफगानिस्तान के अंतिम राजा मोहम्मद जहीर शाह को उनके चचेरे भाई मोहम्मद दाउद खान ने तख्तापलट कर दिया था जबकि इटली में उनकी सर्जरी हुई थी।
1974 लंदन टॉवर में हुए बम धमाके से 41 लोग घायल हो गए।
1981 अमेरिका के मिसौरी के कैनसस सिटी के हयात रीजेंसीहोटल में एक संरचनात्मक असफलता के कारण एक पैदल मार्ग गिर गया, जिसमें से (क्षति का चित्रण) 114 लोगों की मौत हो गई और 216 अन्य घायल हो गए।
1992 महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने आधिकारिक तौर पर मैनचेस्टर मेट्रोलिंक, ग्रेटर मैनचेस्टर, इंग्लैंड में एक हल्की रेल प्रणाली खोली।
1994 धूमकेतू शुमेकर लेवी-9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति से टकराया।
1995 नास्डैक कम्पोजिट इंडेक्स पहली बार 1,000 अंक से ऊपर बंद हुआ।
1996 टीडब्ल्यूए फ्लाइट 800 ने मध्य-हवा में विस्फोट किया और पूर्वी मोरीचेस, न्यूयॉर्क के पास अटलांटिक महासागर में गिर गया।
2006 कैप कनैवरल (फ्लोरिडा) के स्पेस सेंटर में अपनी 13 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर डिस्कवरी अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर सकुशल उतरा।
2009 दो आत्मघाती हमलावरों ने इंडोनेशिया के दो अलग-अलग होटल जकार्ता में खुद को विस्फोटित कर लिया।
2010 दक्षिण कोरिया एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल विकसित करता है जो कथित तौर पर उत्तर कोरिया, जापान, रूस और चीन को टक्कर देने में सक्षम है।
2011 उरुग्वे के पूर्व तानाशाह जुआन मारिया बोरदाबेरी की तानाशाही के दौरान हुई हत्याओं के लिए गिरफ्तारी के दौरान मृत्यु हो जाती है।
2011 केसी एंथोनी, अपनी बेटी केली की हत्या की मंजूरी दे दी और ऑरेंज काउंटी, फ्लोरिडा जेल से रिहा होने के लिए तैयार हो गया, फैसले से नाखुश भीड़ को आकर्षित करता है।
2012 शीर्ष कार्यकारी मारिसा मेयर, याहू नियुक्त होने के बाद गूगल छोड़ देती हैं! इंक का नया सीईओ।

तीन साल में योगी आदित्यनाथ कितने बदल पायेंगे हालात

अजय कुमार

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान उठाना पड़ा। यूपी की वजह से केंद्र में मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, जो बीजेपी यूपी में 80 सीटें जीतने का सपना पाले हुए थी, वह 33 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी का ग्राफ इतनी तेजी से गिरा की अब तो विपक्षी नेता खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो दिल्ली में मोदी को सबक सिखाने के पश्चात तीन साल बाद 2027 में योगी को भी धूल चटाने की बात करने लगे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं और तब योगी की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। 2027 के चुनाव में जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान में उतरेंगे, वहीं बीजेपी को 2024 के नतीजे कचोटते रहेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2024 जैसे चुनावी नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव में नहीं देखना चाहती है। इसीलिये बीजेपी आलाकमान के साथ-साथ सीएम योगी आत्यिनाथ उन मुद्दों की धार कुंद करने में लग गये हैं जिसके सहारे कांग्रेस-सपा गठबंधन ने बीजेपी को आईना दिखाया था।

लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने संविधान, दलित ओबीसी आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत चुनावी हथियार बनाया था। अबकी से राहुल के मुंह से अडानी-अंबानी, नोटबंदी, राफेल विमान खरीद भ्रष्टाचार, चौकीदार चोर है, जैसे तमाम जुमले सुनने को नहीं मिले थे। राहुल गांधी के साथ-साथ अखिलेश यादव भी अपनी जनसभाओं में दो ही बातें दोहराते रहे, पहला मोदी को 400 सीटें मिली तो वह संविधान बदल देंगे, दूसरा दलितों और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर दिया जायेगा। इसके अलावा राहुल की महिलाओं को 8500 रूपये प्रति माह देने की गारंटी ने भी बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। चुनाव बाद भी जिस तरह से राहुल गांधी संविधान की किताब लिये घूम रहे हैं उसकी काट के लिये अब मोदी सरकार ने इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। मोदी के मंत्री से लेकर छोटे-बड़े सभी नेता लगातार बता रहे हैं कि 1975 में किस तरह से तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाकर संविधान की आत्मा को तार-तार कर दिया था। सदन में तो इमरजेंसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक पास हो गया। सबसे खास बात यह रही कि मोदी सरकार जब इमरजेंसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाई तो इसके खिलाफ कांग्रेस सदन में अकेले ही खड़ी नजर आई। राहुल के सबसे मजबूत साथी समझे जाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इमरजेंसी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं गये।

बहरहाल, आम चुनाव में इंडी गठबंधन के कुछ दमदार और असरदार साबित हुए मुद्दों की धार को मोदी सरकार कम करने में लगी है तो दूसरी ओर गठबंधन के कुछ मुद्दों की हवा निकालने के लिये योगी सरकार ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रखी है। योगी ने इसके लिये अभी से सरकार के पेंच कसना शुरू कर दिये हैं। संगठन स्तर पर भी काम चल रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के शुरुआती तीन-चार महीनों में सम्पन्न होना है। इस हिसाब से सरकार के पास तीन साल से भी कम का समय बचा है। यह तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी खराब छवि वाले विधायकों का टिकट काटने में भी आलाकमान परहेज नहीं करेगा। गौरतलब हो, हाल में सम्पन्न लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से काफी कम सीटें मिली थीं। चुनाव आयोग ने जो आकड़े जारी किये हैं उसके अनुसार यूपी में 80 लोकसभा सीटें जिसके अंतर्गत 403 विधान सभाएं आती हैं,वहां अबकी से बीजेपी 162 विधान सभा क्षेत्रों में समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी से पिछड़ गई थी। इन 162 विधान सभा क्षेत्र के विधायकों पर भी गाज गिर सकती है।

वहीं 2027 में विपक्ष एक बार फिर से बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बना पाये इसके लिये

योगी ने सभी खाली पड़े रिक्त पदों को भरने के लिये बम्पर नौकरियां निकाली हैं। अभी एक लाख नौकरियां निकाले जाने की बात कही जा रही है जिसका आंकड़ा 2027 के विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने तक पांच लाख तक पहुंच सकता हे। इसी के साथ पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने और इसमें लिप्त अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिये भी एसटीएफ तेजी से काम कर रही है। बेरोगारी और पेपर लीक की घटनाओं के चलते युवा वर्ग केन्द्र और राज्य सरकारों के खिलाफ काफी आक्रोशित है। उधर, इन युवाओं को गुस्से को विपक्ष हवा-पानी देने का काम कर रहा है। ऐसी ही एक मोदी सरकार की एक और योजना अग्निवीर भी सरकार के लिये बढ़ा मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष लगातार इसे खत्म करने की मांग कर रहा है। इस योजना का दुष्प्रभाव मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में देख भी चुकी है। कुल मिलाकर योगी सरकार बम्बर नौकरियां निकाल कर विपक्ष को उसकी बेरोजगारी वाली सियासत से 'बेरोजगार' करना चाहती है।

बात सरकार से हटकर संगठन स्तर की कि जाये तो लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली चोट भाजपा को बेचैन किए हुए हैं। योगी की छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार के गठन के बाद भाजपा के जिम्मेदार अब यूपी में पार्टी के ग्राफ गिरने के कारणों की पड़ताल पर लगा है। पार्टी स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चैधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने वोट में आई गिरावट को लेकर चर्चा की। तय किया गया है कि भाजपा के पक्ष में कम मतदान की जांच होगी। दरअसल, यूपी के चुनाव परिणाम से भाजपा के स्थानीय से लेकर शीर्ष नेतृत्व में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार करीब नौ फीसदी कम वोट मिले हैं। अब इन्हीं वोट का पता लगाने को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है कि आखिर यह वोट भाजपा से छिटक कर कहां गया। इसका पता करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें संगठन के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। फोर्स के सदस्य गांव-गांव जाकर यह पता लगाएंगे कि भाजपा के कोर वोटर माने जाने वाले ओबीसी और दलितों में सेंध किस दल ने लगाया है। यह भी पता लगाया जाएगा कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को भाजपा से बिदकाने में किन-किन लोगों का हाथ है। साथ ही भितरघात करने वाले पार्टी नेताओं का भी पता किया जाएगा। केंद्र में भले ही लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है लेकिन पार्टी के लिए सबसे मजबूत सियासी जमीन यूपी में खिसकने की टीस सभी नेताओं को हो रही है। इसलिए अब पार्टी ने नुकसान पहुंचाने वालों के साथ उन मतदाताओं के बारे में भी पता लगाने का फैसला किया गया है कि जो इस बार भाजपा के बजाए विपक्ष की तरफ खिसक गए हैं। यूपी में बीजेपी का ग्राफ गिरने की पूरी समीक्षा के बाद यूपी बीजेपी में संगठन स्तर पर भी कई बदलाव हो सकते हैं। यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है और यह दलित अथवा पिछड़ा समाज को हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। वैसे कयास यह भी लगाये जा रहे हैं कि योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर संगठन में आना चाह रहे हैं। मौर्य के यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहते 2014 में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था।

भाजपा इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि वर्ष 2017 में रिकॉर्ड 312 विधानसभा सीटों और 2022 के विधान सभा चुनाव में भी भगवा परचम लहराकर बहुमत की सरकार बनाने वाली भाजपा अबकी लोकसभा चुनाव में 162 सीटों पर ही कैसे पिछड़ गई। वहीं 2017 में कांग्रेस से हाथ मिलाने पर भी 47 सीटों पर सिमटकर सत्ता गंवाने वाली सपा इस चुनाव में सर्वाधिक 183 सीटों पर आगे रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ दो विधायक वाली पार्टी बनी कांग्रेस, लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन कर 40 विधानसभा सीटों पर अव्वल आई। वैसे सच्चाई यह भी है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से यूपी में एनडीए का ग्राफ लगातार गिर रहा था, लेकिन इस ओर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। एनडीए के सहयोगी अपना दल (एस) व सुभासपा संग सरकार बनाने वाली भाजपा को पहला झटका 2019 के लोकसभा चुनाव में लगा। तब सपा-बसपा-रालोद के मिलने पर भाजपा के सांसद जहां 71 से घटकर 62 रह गए। वहीं पार्टी 274 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त बना सकी थी। 2019 में सपा के पांच सांसद जीते और पार्टी 44 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, जबकि 10 सांसद वाली बसपा 66 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। सिर्फ रायबरेली लोकसभा सीट जीतने वाली कांग्रेस मात्र नौ सीटों पर ही औरों से आगे निकली थी। इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा यूपी में फिर सरकार बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन उसकी सीटों और घट गई। भाजपा इस चुनाव में सिर्फ 255 सीटें ही हासिल कर सकी थी। रालोद व सुभासपा को साथ लेने से भी सपा पांच वर्ष बाद सरकार में वापसी तो नहीं कर सकी, लेकिन उसकी सीटें जरूर 47 से 111 हो गईं। सपा से हाथ मिलाने पर रालोद के आठ व सुभासपा के छह विधायक भी जीते। इसी तरह भाजपा के साथ रहने पर अपना दल (एस) के 12 विधान सभा उम्मीदवार जीते। अकेले चुनाव लड़ी कांग्रेस दो और बसपा एक ही सीट जीत सकी थी। यहां तक तो 'भगवा दल' के लिए किसी तरह के बड़े सियासी खतरे के संकेत नहीं थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के आए नतीजे हर लिहाज से सत्ताधारी भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हुए। 2024 लोकसभा चुनाव में घटते जनाधार के कारण भाजपा के जहां मात्र 33 सांसद रह गए है। वहीं विधानसभा सीटों पर भी दबदबा घट गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 255 सीटें जीतने वाली भाजपा को इस बार सिर्फ 162 सीटों पर ही बढ़त मिली है। सपा के साथ छोड़ फिर एनडीए के साथ आया रोलाद तो दो सांसदों के साथ आठ विधानसभा सीटों पर आगे रहा लेकिन एक सीट गंवाने वाला अपना दल (एस) सिर्फ चार विधानसभा क्षेत्रों में ही आगे है। सपा के अबकी कांग्रेस से हाथ मिलाने पर 37 सांसद तो जीते ही, उसे सर्वाधिक 183 विधानसभा सीटों पर बढ़त भी मिली है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों के नेता न केवल उपचुनाव बल्कि अगला विधानसभा चुनाव भी साथ-साथ लड़ने की बात कहे रहे है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में भाजपा के एनडीए और कांग्रेस-सपा के आइएनडीआइए के बीच हुई लड़ाई को अगर विधानसभावार देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन, सत्ताधारी एनडीए पर बहुत भारी दिखता है। एनडीए को जहां 174 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली वहीं विपक्षी गठबंधन 224 सीटों पर आगे रहा है। 50 सीटों पर आगे रहना वाला विपक्षी गठबंधन, राज्य में सरकार बनाने के लिए जरूरी 202 सीटों के जादुई आंकड़े से कहीं अधिक है। इसी चिंता से मोदी-योगी और बीजेपी मुक्ति चाहते हैं। योगी लगातार भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में जोश भरने का काम कर रहे योगी अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में विरोधियों के दुष्प्रचार और भ्रम जाल में फंसकर कई वोटर भाजपा से दूर चले गये थे, जिनको वापस अपने पाले में लाना होगा। मुख्यमंत्री ने बूथ स्तरीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि रूठे लोगों के मनाएं और उन्हें दोबारा भाजपा के साथ मजबूतों से जोड़ें। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बूथ प्रभारी अपने-अपने बूथ पर मिले वोटों की समीक्षा करें। 2017 और 2022 के विधानसभा और 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले वोटों के आधार पर नए सिरे से रणनीति बनाकर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाएं। स्वयं समीक्षा करें कि वोटों का अंतर क्यों कम हुआ है। जो कारण मिले उसे दूर करने की दिशा में काम करें।

जनप्रतिनिधि निभाएं रचनात्मक भूमिका

गिरीश्वर मिश्र

पूरे देश की जनता ने बड़ा भरोसा जताते हुए अपने 543 प्रतिनिधि चुनकर 18 वीं लोकसभा में भेजे हैं। उनकी आशा है ये सांसद देश की भलाई के लिए नीति और कायदे बनाएं, उसे लागू कराएं और जन-जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं। संसद की सदस्यता की शपथ लेते समय सांसद गण इन सब बातों को ध्यान में रखने की कसम भी खाते हैं। यह भी गौरतलब है कि हमारी संसद लोकतंत्र के वैचारिक शिखर और देश की संप्रभुता को भी द्योतित करती है। इसलिए उसकी गरिमा बनाए रखना सबका कर्तव्य बनता है। इसके लिए कार्य करने का दायित्व धारण करने वाले जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा होती है कि वे संसद की बैठकों में नियमित भाग लें और सार्थक बहस करें। चूंकि जनता के समर्थन से ही वे सांसद का दर्जा पाते हैं इसलिए संसद तक पहुंचने की कठिन यात्रा पूरी कर उसकी देहरी लांघ उनको सिर्फ आम जनता की नुमाइंदगी करनी होती है। यही उनका फर्ज बनता है। लोकसभा की सदस्यता पांच साल की और राज्यसभा की छह साल की होती है और इस दौरान सांसद से अपना लोक-दायित्व इस पूरी अवधि में निभाना अपेक्षित होता है। बजट, मानसून और शीतकालीन ये तीन मुख्य सत्र होते हैं। बैठक में प्रश्नकाल और शून्यकाल की व्यवस्था भी होती है। उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए खास मौकों पर सांसदों की घेरेबंदी करनी पड़ती है। उनको पकड़ में बनाए रखने के लिए पार्टियों द्वारा व्हिप जारी किया जाता है। इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि पहली लोकसभा की बैठक वर्ष में 135 दिन आयोजित हुई थी। सात दशक बाद सत्रहवीं लोकसभा तक आते-आते स्थिति कितनी नाजुक हो गई। इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि कुल 55 दिन की बैठक का ही औसत रहा। कोविड के कारण सन 2020 में कुल 33 दिन ही बैठक हुई। सन 1952 के बाद सबसे कम संसदीय काम सत्रहवीं लोकसभा में हुआ। (लगभग) बिना विचार किए बिल पास करने की प्रथा भी चल निकली। 35 प्रतिशत बिल एक घंटे से कम की चर्चा के बाद पास हुए। अब बिल स्टैंडिंग कमेटी को भी नहीं जाते; कुल 16 प्रतिशत बिल ही उसके पास विचार हेतु भेजे गए।

अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से मिली जमानत के निहितार्थ

सुरेश हिंदुस्तानी

देश की राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर चल रही राजनीति ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत देकर जांच एजेंसी पर उठे संदेह के घेरे को और बड़ा कर दिया है। अरविन्द केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश का पर्दाफाश बताया है। यहां एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या न्याय व्यवस्था में जमानत मिलना विजय का पर्याय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसे अपनी विजय और सरकारी एजेंसी की साजिश करार दे रही है। उल्लेखनीय है कि जमानत मिलने के बाद भी आरोप समाप्त नहीं हो जाता। प्रकरण चलता रहता है। अभी शराब घोटाले में न्यायालय का निर्णय नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति इसे निर्णय मानकर चल रही है। आम आदमी पार्टी का यह कदम वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने जैसा ही माना जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रारम्भ से ही यह बताने की कवायद की जा रही है कि शराब मामले में कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। उनका तर्क है कि अगर घोटाला हुआ है तो उस घोटाले की राशि भी जब्त की जानी चाहिए, जबकि प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि इससे जो राशि प्राप्त हुई उसे गोवा के चुनाव में व्यय किया गया। दोनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूंठ, यह आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन इसी मामले में आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भी आरोपी हैं, उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल सकी है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि घोटाला हुआ ही नहीं। हो सकता है कि यह घोटाला बहुत चतुराई के साथ किया हो, क्योंकि प्रमाण पर्याप्त नहीं हैं। केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर आम आदमी पार्टी भले ही खुशियाँ मना ले, लेकिन यह सत्य है कि न्यायालय ने उनके मुख्यमंत्री के अधिकार सीमित कर दिए हैं। उनको न तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार है और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

किसी भी घोटाले की जांच के लिए जांच एजेंसी कार्य करती हैं। लेकिन शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसी पर संदेह के बादल भी उमड़ रहे हैं। हो सकता है कि जांच एजेंसियां अपनी भूमिका को लेकर एकदम सही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविन्द केजरीवाल की गिरफ़्तारी के बाद जांच एजेंसी को विलेन के रूप में

प्रचारित करने का अभियान सा चलता दिखाई दिया। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जांच एजेंसियों पर पहले भी सत्ता के इशारे पर कार्य करने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती हैं, लेकिन जांच एजेंसियों पर यह आरोप लगाना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य कर रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी अपने नेता अरविन्द केजरीवाल की गिरफ़्तारी की साजिश करने में जांच एजेंसी से अधिक भाजपा को निशाने पर लेने की राजनीति कर रही है। ऐसा नहीं है कि केवल आम आदमी पार्टी ही राजनीति कर रही है, बल्कि भाजपा भी कम नहीं है, वह भी इस मामले में बयान देने से पीछे नहीं है।

जहाँ तक भाजपा की बात है तो वह केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहले ही कह चुकी है कि न खाऊँगा और न खाने दूंगा। इस बात को ध्यान में रखकर यही कहा जा सकता है कि भाजपा की केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के विरोध में कार्यवाही करना चाहती है, लेकिन विपक्ष के राजनीतिक दल इसमें टांग अड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि विपक्ष के अधिकांश बड़े नेता किसी न किसी आरोप में जमानत पर बाहर हैं। कई नेताओं पर गंभीर आरोप हैं और कई जेल में हैं। इसलिए विपक्ष और खास कर आम आदमी पार्टी के कदम को सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। हम जानते ही हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता हैं। लेकिन इसके बाद भी वे बिहार और देश की सक्रिय राजनीति में दखल दे रहे हैं। आज हालांकि लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि सजा प्राप्त कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। सवाल यह है कि क्या ऐसा व्यक्ति राजनीति कर सकता है। नहीं करना चाहिए, लेकिन लालू ऐसा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने केवल राजनीति ही नहीं की, बल्कि विपक्ष के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर खड़े दिखाई दिए। इस प्रकार की राजनीति करना किसी भी दल के लिए भी ठीक नहीं और देश के लिए भी ठीक नहीं मानी जा सकती। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर का हो, जिसने भी किया है, उसके विरोध में कार्यवाही होना ही चाहिए। आम आदमी पार्टी भी यही कहकर दिल्ली की सत्ता पर विराजमान हुई थी। जो अब अपने सिद्धांत से परे जाती हुई दिखाई दे रही है।

हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राजनीति प्रारम्भ करने से पूर्व अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उस समय कांग्रेस की केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के कारण पूरा देश उबाल में था। इसी कारण अन्ना हजारे के आंदोलन को व्यापक रूप से सफलता मिली। इसके बाद एक ईमानदार राजनीतिक दल के रूप में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई। बड़े बड़े वादे करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में छप्पर फाड़ समर्थन प्राप्त करके सरकार बना ली। लेकिन इसके बाद क्या हुआ। ज़ब इनको सत्ता की चासनी चखने को मिली तो यह बौरा गए और फिर वही खेल शुरू हो गया जो चलता आया है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार करने के जो आरोप लगे हैं, वह अभी जांच की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जांच होने के बाद यह तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में हैं।

दिल्ली के शराब घोटाले में जिस प्रकार से साजिश की बात कही जा रही है, उससे यह तो कहा जा सकता है कि इसमें साजिश हो सकती है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार साबित होते हैं तो यह भी एक साजिश ही मानी जाएगी, लेकिन अगर अरविन्द केजरीवाल को फंसाया गया है तो यह गंभीर साजिश ही कही जाएगी। फिलहाल इस मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब यह मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। जिसकी परतें उधड़ना बाकी हैं। अंदर क्या निकलता है, इसे देखने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।

उपचुनाव में जाटों को कौन साध सकेगा अबकी बार?

शाहरुख खान

अलीगढ़ जिले का जाटलैंड कही जाने वाली खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी हो रही है। हर दल अपने-अपने स्तर से प्रयासरत हैं। सभी के सामने सवाल है कि अबकी बार इस सीट पर बहुसंख्यक जाटों को कौन साधेगा। भाजपा तीसरी बार फिर जीत के लिए प्रयासरत है। लोकसभा के परिणामों को देखकर सपा भी उत्साहित है। अब परिणाम क्या होगा? यह तो आने वाला समय बताएगा। मगर सभी दलों और टिकट के दावेदारों ने अपने-अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।

आजादी के बाद 1957 में अस्तित्व में आई टप्पल और अब खैर विधानसभा सीट पर जाट बहुल होने के कारण चौधरियों का कब्जा रहा है। इसी वजह से इसे जिले का दूसरा जाटलैंड कहा जाता है। सबसे पहले बसपा के सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले ने चौधराहट पर ब्रेक लगाया और 2002 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े ब्राह्मण नेता प्रमोद गौड़ ने जीत दर्ज की।

2007 में रालोद के चौ. सत्यपाल सिंह के सामने वह चुनाव हार गए। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित हो गई। इतिहास पर गौर करें तो खैर, चंडौस, टप्पल व जवां का इलाका एक विधानसभा का हिस्सा था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहनलाल गौतम यहां से विधायक थे। 1957 में इसे अलग टप्पल सीट का दर्जा मिला और टप्पल क्षेत्र के गांव मालव के रहने

वाले कांग्रेस नेता चौ. देवदत्त सिंह पहले विधायक बने।

राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इस सीट पर जाटों के बीच चौ. चरण सिंह का बड़ा प्रभाव रहा। इस वजह से शुरुआत में कांग्रेस, फिर बीकेडी, जेएनपी और हाल के दिनों में रालोद के विधायक रहे। मगर, यहां पार्टी के साथ-साथ निजी व्यवहार, संबंध और लोगों के बीच गहरी पैठ रखने वाले नेता विधायक बने हैं। मतलब लोगों के बीच जिसके बेहतर रिश्ते, उसका वर्चस्व रहा है।

इस सीट पर 1974 व 1977 में चौ. प्यारेलाल व 1985 व 1989 में जगवीर सिंह ही दोबारा विधायक बने हैं। इनके अलावा, भाजपा के अनूप प्रधान 2017 व 2022 में यहां से विधायक चुने गए।

लखनऊ में रविवार को भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इस बैठक में जिले से सांसद व विधायक सहित जनप्रतिनिधि, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और जिला व महानगर अध्यक्ष मौजूद रहे।

इस दौरान लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर बिना किसी घबराहट के आने वाले चुनावों की तैयारी में जुटने का आह्वान किया गया। मंडल स्तर तक कार्यसमिति की बैठक का लक्ष्य रखा गया। उप चुनाव की तैयारियों में सभी से जुटने के लिए कहा गया। किसी भी कीमत पर सीट चाहिए। इसी प्रयास में काम करना है।

ये है इतिहास

1952 में कांग्रेस से मोहनलाल गौतम (टप्पल, खैर, चंडौस, जवां संयुक्त विधानसभा क्षेत्र)। 1957 में कांग्रेस से चौ. देवदत्त सिंह (टप्पल विधानसभा क्षेत्र बना)। 1962 में निर्दलीय चौ. महेंद्र सिंह। 1967 में कांग्रेस से चौ. प्यारेलाल (खैर विधानसभा क्षेत्र बना)। 1969 में भारतीय क्रांति दल से चौ. महेंद्र सिंह। 1974 में कांग्रेस से चौ. प्यारेलाल। 1977 में जेएनपी से चौ. प्यारेलाल। 1980 में कांग्रेस से चौ. शिवराज सिंह। 1985 में लोकदल से चौ. जगवीर सिंह। 1989 में जनता दल से चौ. जगवीर सिंह। 1991 में बीजेपी से चौ. महेंद्र सिंह। 1993 में जनता दल से चौ. जगवीर सिंह। 1996 में भाजपा से ज्ञानवती सिंह पुत्री चौ. चरण सिंह। 2002 में बसपा से प्रमोद गौड़। 2007 में रालोद से चौ. सत्यपाल सिंह। 2012 में रालोद से भगवती प्रसाद सूर्यवंशी। 2017 में भाजपा से अनूप प्रधान। 2022 में भाजपा से अनूप प्रधान।

उपचुनाव परिणाम भाजपा के लिए चिंताजनक

राजकुमार सिंह

लोकसभा चुनाव के बाद सात राज्यों में हुए 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी मतदाताओं ने भाजपा और उसकी अगुवाईवाले राजग को झटका दिया है। भाजपा (या राजग) मात्र दो सीटें जीत पाई है, जबकि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' उससे पांच गुना यानी 10 सीटें जीतने में सफल रहा है। शेष एक सीट रूपौली से निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। इसी साल 19 अप्रैल से एक जून के बीच हुए 18 वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा केंद्रीय सत्ता की 'हैट्रिक' करने में तो सफल रही, लेकिन उसकी अपनी सीटें 303 से घट कर 240 रह गईं और बहुमत के लिए उसे तेलुगु देशम पार्टी एवं जनता दल यू जैसे सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस 99 और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' मिल कर 234 सीटें ही जीत पाया। इसलिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव में लगे झटके को भी अपनी जीत और जनता का आशीर्वाद बताया, लेकिन इन विधानसभा उपचुनाव नतीजों ने फिर खतरे की घंटी बजा दी है कि जमीन पर उसके लिए सब कुछ ठीक नहीं है। ये नतीजे किसी एक राज्य के नहीं, बल्कि सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के हैं, इसलिए इन्हें हल्के में लेने की गलती भाजपा को नहीं करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, जहां वह लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतने में सफल रही थी। हिमाचल में पर्याप्त विधायक न होने के बावजूद भाजपा ने राज्यसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस और उसके समर्थक निर्दलीय विधायकों में तोड़फोड़ की थी। उन्हीं तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के चलते ये उपचुनाव हुए। भाजपा ने उन तीनों निर्दलीय विधायकों को अपने टिकट पर उपचुनाव लड़वाया, लेकिन दो सीटों पर कांग्रेस बाजी मार ले गई। पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में जालंधर सीट पर तीसरे स्थान रहने की शर्मिंदगी झेलने के बाद सत्तारूढ़ आप और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब उपचुनाव में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट जीत कर अपना सम्मान बचा लिया है। भाजपा को सबसे बड़ा झटका प. बंगाल में लगा है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से लगातार मात खा रही भाजपा पहले तो लोकसभा चुनाव में अपनी पिछली सीट संख्या भी बरकरार रखने में नाकाम रही और अब चार विधानसभा सीटों के उपचुनाव में खाली हाथ रही। इनमें से तीन उपचुनाव की नौबत तो भाजपा विधायकों के इस्तीफा देने से ही आई थी। एक अन्य सीट पर तृणमूल विधायक के निधन के चलते उपचुनाव कराना पड़ा। उपचुनाव में चारों सीटें तृणमूल के खाते में गई हैं। वैसे 13 में से तीन सीटें ही भाजपा के पास थीं, इसलिए तकनीकी रूप से उसे एक सीट का नुकसान हुआ है, पर कुल परिणाम का राजनीतिक संदेश उसके लिए नकारात्मक है।

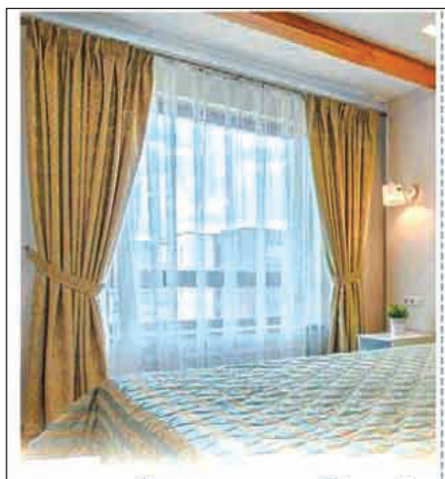

घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ऐसे सजाएं खिड़कियां

घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम सभी चीजों की सजावट करते हैं लेकिन कई लोग खिड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। खिड़कियां की साफ- सफाई के साथ इसकी सजावट करना भी काफी ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप भी खिड़कियां की सजावट करना चाहती हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप इसकी सजावट कैसे कर सकती हैं।

खिड़कियां की सजावट करने से पहले आपको उसे अच्छे तरीके से साफ करना होगा। अगर आप अपने खिड़कियों की सजावट सही तरीके से करना चाहती हैं तो आपको खिड़की पर लगी धूल को साफ करना होगा। धूल निकालने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से सजा सकती हैं।

स्टफ टॉयज का करें इस्तेमाल

अपनी खिड़की को सजाने के लिए आप चाहे तो स्टफ टॉयज का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके खिड़की पर जगह है तो आपको उस पर स्टफ टॉयज रखना होगा। स्टफ टॉयज देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है।

पौधे से करें सजावट

खिड़कियां अगर बड़ी है तो आपको अपने घर की खिड़कियों को सजाने के लिए हैंगिंग प्लांट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी मदद से आप अपने घर के खिड़कियों की मिनटों में सजावट कर सकती हैं। यह काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा।

कर्टेन सही चुनें

कर्टेन आपके घर की खिड़कियों की रौनक को बढ़ा सकता है। ऐसे में आपको अपने घर के खिड़कियों की सजावट करने के लिए लाइट कलर के कर्टेन लगाने होगे। इसकी मदद से आप आसानी से अपने घर के खिड़कियों को सजा सकती हैं।

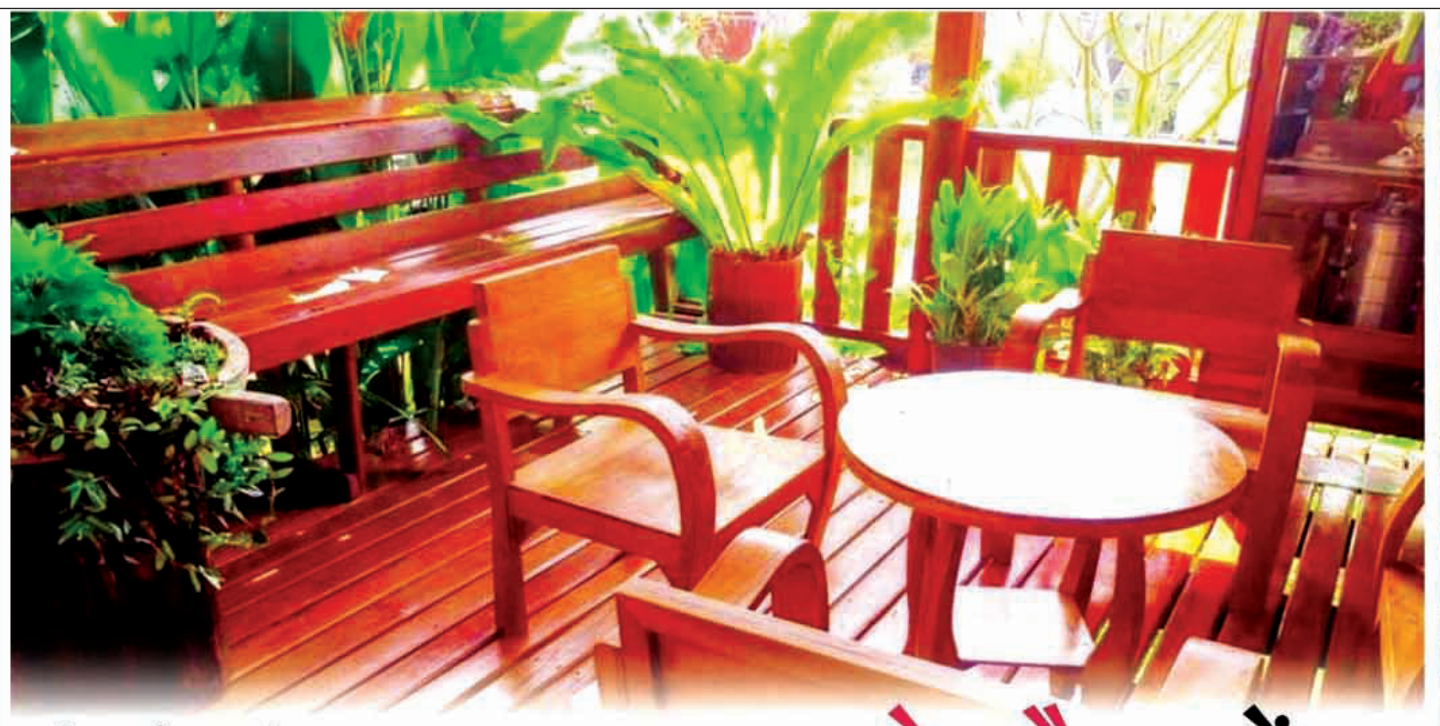

बरसात के मौसम में घर के फर्नीचर को सेफ रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

बारिश का मौसम अपने साथ तरह-तरह की परेशानियां लेकर ही आता है। रोड पर जलजमाव के कारण कहीं आने-जाने में दिक्कत से लेकर घर की साफ-सफाई तक हर कुछ में इस दौरान समस्याएं बढ़ जाती है। ऐसा ही एक दिक्कत घर में मौजूद फर्नीचर के साथ भी होता है। दरअसल, बरसात के दिनों में लकड़ी के फर्नीचर में भी नमी आ जाती है। यही नहीं, इसके कारण सड़न और दीमक लगने की भी संभावनाएं काफी बढ़ जाती है, लेकिन आपको अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आज एक्सपर्ट के बताए कुछ आसान से टिप्स बताने वाले हैं, जिसे फॉलो करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं।

फर्नीचर को ढक कर रखें

अगर यह खिड़की या बालकनी के पास रखी है तो आप अपने फर्नीचर ढक कर रख सकते हैं। इसके लिए प्लास्टिक शीट या वाटरप्रूफ कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने फर्नीचर को पानी और नमी से बचा सकते हैं। इसके अलावा, सोफों और कुर्सियों को फैब्रिक कवर से भी आप ढक सकते हैं।

अपने फर्नीचर को धूप में सुखाएं

फर्नीचर में नमी को बनने से रोकने के लिए संभव हो तो इसे धूप में जरूर सुखाएं। इससे पानी का असर फर्नीचर पर नहीं होगा और न ही इसमें दीमक आदि लगने की स्थिति बन पाएगी।

लकड़ी के फर्नीचर को पेंट या पॉलिश करें

पानी और नमी से फर्नीचर को बचाने के लिए आप एक सुरक्षात्मक परत बना सकते हैं। इससे फर्नीचर की चमक बरकरार रहेगी ही। साथ ही, बरसात में ये खराब होने से भी बच सकते हैं।

फर्नीचर को दीवारों से दूर रखें

नम दीवारों से फर्नीचर में नमी आ सकती है। ऐसे में फर्नीचर और दीवारों के बीच थोड़ा गैप रखना जरूरी है। इसके अलावा, नमी के स्तर को कम करने और लकड़ी के फर्नीचर को सुरक्षित रखने के लिए कमरे में डीह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हैं।

रबर पैड का करें इस्तेमाल

गंदे और गीले फर्श के साथ सीधे संपर्क में आने से फर्नीचर पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रखने के लिए पैरों के नीचे रबर पैड लगा सकते हैं।

फर्नीचर को कैसे रखें साफ?

- धूल और गंदगी को जमा होने से रोकने के लिए अपने फर्नीचर को नियमित रूप से साफ करते रहें।
- इसपर कवर, कोस्टर या पैड को बिछाकर रखें।
- अपने फर्नीचर को सीधे धूप से बचाएं।
- लकड़ी के फर्नीचर को महीने में एक बार घरेलू तरीके से जरूर पॉलिश करें।
- कपड़े के फर्नीचर को वैक्यूम क्लीनर से साफ करते रहें।

बिना खर्च किए इस तरीके से बनाएं फर्नीचर क्लीनिंग स्प्रे

महंगे फर्नीचर की खास केयर की जरूरत होती है। इसके लिए बाजार में आपको यूं तो कई सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पर, आप चाहें तो केमिकल मुक्त घर पर ही क्लीनिंग स्प्रे तैयार कर सकती हैं।

फर्नीचर क्लीनर स्प्रे बनाने की सामग्री

1 कप सफेद सिरका, 2 कप पानी
2 चम्मच नींबू का रस
1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, स्प्रे बोतल

घर पर फर्नीचर क्लीनर कैसे बनाएं?

- फर्नीचर क्लीनर तैयार करने के लिए सबसे पहले एक स्प्रे बोतल में सफेद सिरका और पानी डालें। आप चाहें तो सिरके की जगह नींबू का रस भी डाल सकती हैं।
- अब इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल डालें। यह आपके फर्नीचर पर पॉलिश का काम करेगा।
- इसके बाद, बोतल को अच्छी तरह हिलाएं।
- बस लीजिए, आपका फर्नीचर क्लीनिंग स्प्रे तैयार है।
- फर्नीचर क्लीनर का कैसे करें इस्तेमाल?
- स्प्रे बोतल को अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लें।
- इसके बाद, एक मुलायम कपड़े को इस स्प्रे से गीला करें।
- फर्नीचर की सतह को अच्छी तरह पोंछ लें।
- अगर दाग एक बार में न मिटे, तो इसे फिर से दोहराएं।
- आप इस स्प्रे को लकड़ी, प्लास्टिक, धातु और कांच सहित विभिन्न प्रकार के फर्नीचर पर उपयोग कर सकते हैं।

फर्नीचर स्प्रे बनाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

- यदि आप एक स्ट्रॉन्ग क्लीनर चाहते हैं, तो आप सिरके की मात्रा को 1/2 कप तक बढ़ा सकते हैं।
- स्प्रे को सुगंधित बनाने के लिए आप नींबू का रस या चंदन के तेल की मात्रा को 20 बूंद तक डाल सकते हैं।
- यदि आप एक चमकदार फिनिशिंग चाहते हैं, तो ऑलिव ऑयल की मात्रा को भी 2 बड़े चम्मच तक बढ़ा सकते हैं।
- बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें।

इन्वर्टर की बैटरी खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान वर्षों तक नहीं होगी खराब

अगर आप भी घर के लिए इन्वर्टर की बैटरी खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें।
दिन या रात में जब बिजली जाती है तो सबसे पहले ध्यान इन्वर्टर की तरफ जाता है। अगर इन्वर्टर ठीक है तो कई बात नहीं, लेकिन इन्वर्टर की बैटरी डाउन या ख़राब होती है तो अंधेरे में रहना पड़ता है। इसलिए इन्वर्टर की बैटरी सही खरीदना चाहिए। अगर आप भी इन्वर्टर के लिए बैटरी खरीदने जा रहे हैं और यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि इन्वर्टर के लिए बैटरी कैसी होना चाहिए।

बैटरी लेने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

- इन्वर्टर के लिए बैटरी लेना कोइबदी बात नहीं है, लेकिन बैटरी लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है।
- सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आपको कितने घंटे के लिए बैकअप चाहिए।
- आपके घर में लाइट कितनी बार जाती है और कितने देर के लिए जाती है। इसका पूरा अनुमान सेट करके आप आसानी से अच्छी बैटरी खरीद सकते हैं।
- जैसे-पूरे 24 घंटे में लगभग 3 घंटे के लिए बिजली जाती है उसके हिसाब से आप 75-80Ah (एंपीयर/आर) पावर वाली बैटरी खरीद सकते हैं।
- अगर इससे कम या इससे अधिक समय के लिए बिजली जाती है तो आप समय के अनुसार एंपीयर/आर) पावर वाली बैटरी खरीद सकते हैं।

अच्छी बैटरी कैसे सेलेक्ट करें?

मार्केट में मौजूद इन्वर्टर बैटरियों में अच्छी बैटरी कैसे पहचाने ये बड़ा ही सवाल होता है। अगर आप भी इस सवाल में उलझे हुए कि अच्छी बैटरी कैसे सेलेक्ट करें तो फिर आपको कुछ टिप्स को फ़ॉलो करें की ज़रूरत है। जैसे-

- आपको बता दें कि मार्केट में लगभग 3 तरह की बैटरी सबसे अधिक चलती है। फ़्लैट बैटरी, नॉर्मल बैटरी और ट्यूबलर बैटरी अधिक चलती है।
- कई लोगों का मानना है कि ये तीनों बैटरी ही अपने स्थान पर है, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए ट्यूबलर बैटरी अच्छी मानी जाती है। ट्यूबलर बैटरी अधिक समय तक चलती और कम समय में चार्ज भी हो जाती है। इसलिए आप आपने घर के लिए ट्यूबलर बैटरी खरीद सकते हैं।

फ़्लैट बैटरी और नॉर्मल बैटरी कैसी होती है?

यह तो आपको मालूम हो चुका होगा कि इन तीनों बैटरी में से ट्यूबलर बैटरी अच्छी होती है, लेकिन कई लोग फ़्लैट बैटरी और नॉर्मल भी खरीद लेते हैं। ऐसे में इन दोनों बैटरी के बारे में आप भी जन लीजिए। कहा जाता है कि फ़्लैट बैटरी और नॉर्मल बैटरी में कई बार हीटिंग की समस्या होती है जिसके कारण वो जल्दी ख़राब भी हो जाती है। फ़्लैट बैटरी और नॉर्मल बैटरी अधिक समय तक नहीं चलती हैं और कई बार जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। इन दोनों बैटरी के साथ बैकअप की भी समस्या रहती हैं।

इन्वर्टर बैटरी की वारंटी और सर्विस चेक करें

इन्वर्टर बैटरी सेलेक्ट करने के बाद बैटरी की वारंटी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बैटरी की वारंटी 1 साल या फिर 2 तक तक ही होती है, लेकिन अगर आप घर के लिए बैटरी खरीद रहे हैं तो कम से कम 5-7 साल तक की वारंटी वाली ही बैटरी खरीदें। इसके वाला सर्विस के बारे में भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। जी हां, वारंटी के साथ सर्विस के बारे में भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बैटरी किसी वजह से खराब होती है और कंपनी फ्री मेंटेनेंस करती है। इसलिए इन्वर्टर के लिए बैटरी लेते समय वारंटी और सर्विस ज़रूर चेक करें।

बच्चों की स्टेशनरी अक्सर इधर-उधर फैली रहती है। ऐसे में उसे आर्गेनाइज करने के लिए स्टेशनरी आर्गेनाइजर की मदद ली जा सकती है। आप इसे खुद घरेलू आइटम्स की मदद से तैयार कर सकते हैं।

बच्चों के लिए घरेलू आइटम्स की मदद से बनाएं स्टेशनरी आर्गेनाइजर

स्टेशनरी एक ऐसी चीज है, जो लगभग हर घर में होती ही है। जिन घरों में बच्चे होते हैं, वहां तो अक्सर पेन, पेंसिल या कलर आदि अक्सर इधर-उधर रखे हुए नजर आते हैं। अमूमन घरों में मम्मी ही स्टेशनरी को उठाकर बार-बार रखती रहती है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्टेशनरी आर्गेनाइजर का इस्तेमाल करें। स्टेशनरी आर्गेनाइजर की मदद से सभी तरह की स्टेशनरी को एक जगह आसानी से आर्गेनाइज करके रखा जा सकता है। यूं तो आपको मार्केट में कई तरह के अलग-अलग स्टेशनरी आर्गेनाइजर आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे घर पर पुरानी आइटम्स की मदद से भी बेहद आसानी से बना सकते हैं। घर पर स्टेशनरी आर्गेनाइजर बनाना ना केवल बजट फ्रेंडली है, बल्कि आप खुद ही एक यूनिक डिजाइन व साइज का स्टेशनरी आर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बच्चों के लिए घरेलू आइटम्स की मदद से स्टेशनरी आर्गेनाइजर बनाने के तरीके के बारे में बता रहे हैं-

कार्डबोर्ड से बनाएं स्टेशनरी आर्गेनाइजर

- अगर आपके पास पुराने जूते के डिब्बे या कार्डबोर्ड हैं, तो आप उससे स्टेशनरी आर्गेनाइजर बना सकते हैं। आर्गेनाइजर बनाने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स को मनचाहे आकार में काटें। आप आर्गेनाइजर के अलग-अलग सेक्शन बनाने के लिए कार्डबोर्ड को नापकर काट लें।
- अब ग्लू या टेप का उपयोग करके उन्हें चिपका लें। सुनिश्चित करें कि वे मज़बूती से जुड़े हुए हैं। आप तैयार आर्गेनाइजर को डेकोरेटिव पेपर से ढक दें या फिर आप उन्हें पेंट भी कर सकते हैं। अब इसे सूखने दें और फिर तैयार आर्गेनाइजर में स्टेशनरी आइटम को अंदर रखें। पुरानी चीजों को इस्तेमाल करने का आसान तरीका है।

मेसन जार की मदद से बनाएं आर्गेनाइजर

- मेसन जार की मदद से भी स्टेशनरी आर्गेनाइजर तैयार किया जा सकता है। आप अलग-अलग मेसन जार को बतौर आर्गेनाइजर इस्तेमाल करें। इसके लिए आप मेसन जार लें। फिर उसे पेंट करें और सूखने दें। एक जार में सारी स्टेशनरी आर्गेनाइज करना संभव नहीं है, इसलिए आप अलग-अलग मेसन जार को पेंट करें।
- अब आप हर जार में लेबल लगाएं। अगर आपके पास स्पेस की कमी है और आप माउंटेड ऑर्गनाइज़र चाहते हैं, तो स्क्रू और ड्रिल का उपयोग करके लकड़ी के बोर्ड पर होज़ क्लैंप लगाएं। फिर, जार को क्लैंप में सुरक्षित करें। अपने स्टेशनरी आइटम को जार में रखें।

पुरानी प्लास्टिक बोतल से बनाएं आर्गेनाइजर

- घर में पुरानी प्लास्टिक की बोतल होना आम बात है। आप इसे भी बतौर स्टेशनरी आर्गेनाइजर काम में ला सकते हैं। यह इन बोतल को रिसाइकिल करने का एक बेहतरीन तरीका है। आर्गेनाइजर बनाने के लिए प्लास्टिक की बोतलों के ऊपरी हिस्से को मनचाही ऊंचाई पर काटें। सुनिश्चित करें कि किनारे चिकने हों। अगर किनारे नुकीले होंगे तो इससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाएगा।
- अब बोतलों को पेंट करें या उन्हें डेकोरेटिव पेपर से कवर ककर दें। इसी तरह, आप आवश्यकतानुसार बोतलों को तैयार कर लें। इन्हें एक पैटर्न में अरेंज करें और फिर उन्हें गोंद या टेप से सिक्योर करें। आपका स्टेशनरी आर्गेनाइजर बनकर तैयार है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मानहानि मामले पर जल्द फैसला होना राहुल का वैधानिक अधिकार

नई दिल्ली। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में जल्द फैसला पाने का वैधानिक अधिकार है। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चह्वाण की एकल पीठ ने 12 जुलाई को दिए आदेश में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर किसी को तुरंत और स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है। उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले आरएसएस कार्यकर्ता को मामले में नए और अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी थी। मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ ही राहुल ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें थोड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति चह्वाण ने अपने आदेश में कुंटे पर सवाल उठाया और कहा कि उनके आचरण के कारण इस मामले में बेवजह की देरी हो रही है। पीठ ने मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देश दिया कि वह शिकायत पर शीघ्र निर्णय लें और उसका निपटारा करें।

सिसौदिया की जमानत याचिका पर ईडी, सीबीआई को नोटिस

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 29 जुलाई को तय की। सिसोदिया ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े अपने खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत मांगी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं के संबंध में ईडी और सीबीआई द्वारा जांच किए गए अलग-अलग मामलों में जमानत की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर नोटिस जारी किया। सिसौदिया को फरवरी 2023 को सीबीआई ने और बाद में एक महीने बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था और जमानत मांगने के लिए उन्होंने लगभग 16 महीने की कैद का हवाला दिया था।

असम उपचुनाव में कांग्रेस सभी पांच सीटों पर लड़ेगी

नईदिल्ली। कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी राज्य की उन सभी पांच विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी जहां उपचुनाव होने हैं। बोरा ने संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) को लेकर पार्टी के विरोध को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तर के पार्टी नेताओं के साथ हुई बैठक में लिए गए। यह बैठक सिंह की तीन दिवसीय यात्रा के पहले दिन हुई। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और भविष्य के लिए रणनीति बनाने की खातिर जितेंद्र सिंह की योजना सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं के साथ बैठकें करने की है। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं की है। सामागुड़ी, बेहली, धोलाई, सिदली और बोंगाईगांव विधानसभा सीटें, निवर्तमान विधायकों के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद खाली हो गई हैं। इनमें से सिर्फ समागुड़ी सीट कांग्रेस के पास थी।

योगी सरकार के मंत्री संजय ने बुलडोजर नीति पर उठाये सवाल

लखनऊ। लोकसभा चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रदर्शन खराब रहा तो सारा ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जाने लगा। चुनावों में वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मांगे गये थे लेकिन यूपी में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को वोट कम मिलने का सारा भार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर डालने का प्रयास हो रहा है। अब भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी एक तरह से मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कह दिया है कि अगर बुलडोजर चलेगा तो लोग वोट कैसे देंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर हम गरीबों के घर उजाड़ेंगे तो वह हमें उजाड़ देगा। उन्होंने कहा कि यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई से जनता नाराज है। संजय निषाद ने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि आज भी अंदर से कई अधिकारी हाथी, पंजा और साइकिल हैं और जब भी मौका मिलता है यह हमें नीचा दिखा देते हैं।

बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका भी शामिल है। शीर्ष अदालत, जो इस मामले पर उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले से संबंधित 33 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को सूचित किया गया कि कई पक्षों द्वारा प्रतिक्रिया हलफनामा दायर नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी उन मामलों में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है जहां उसे प्रतिवादी बनाया गया है। सीजेआई ने कहा कि ठीक है, हम उन्हें एक मौका देंगे।

जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया: अमित शाह

■ **हरियाणा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री- पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही कांग्रेस**

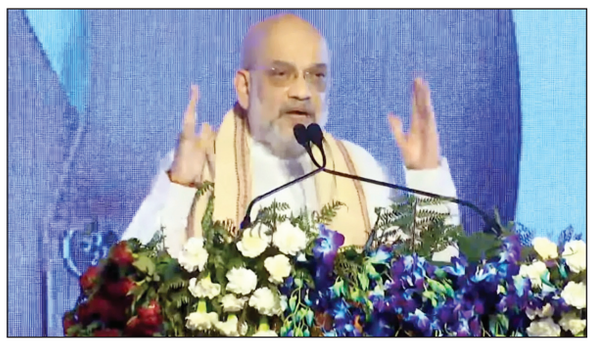

चंडीगढ़। हरियाणा फिलहाल राजनीति के केंद्र में है। इसका बड़ा कारण ये है कि आने वाले महीनों में यहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में आग दिग्गज भाजपा नेता तथा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने भाजपा सरकार के कामकाज को गिनवाया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

अपने संबोधन के शुरूआत में शाह ने कहा कि हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने हमेशा भाजपा को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा का कर्तव्य बनता है कि जितना आपने किया है, उससे ज्यादा कार्य करके हम आपके पास आएं। शाह ने कहा कि नायब सिंह जी की कैबिनेट ने तीन निर्णय लिए हैं -क्रीमी लेयर की लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। इन 8 लाख में तनख्वाह और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था, उसको भी बदलने का फैसला लिया गया है। पंचायतों में अब तक 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे हरियाणा की जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही शाह ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 8 प्रतिशत आरक्षण जस का तस रहेगा और ग्रुप बी को 5% आरक्षण ज्यादा मिलेगा। ये तीनों निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को लागू करने वाले हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश को कहा था कि मेरी ये सरकार दलितों, गरीबों और पिछड़ों की सरकार है। देश को पहला सशक्त पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री देने का काम भाजपा ने किया है। 71 में से 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से देकर नरेन्द्र मोदी जी ने हरियाणा और देश के ओबीसी का सम्मान करने का काम किया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है।

उन्होंने कहा कि 1957 में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए काका कालेलकर कमीशन बना, लेकिन कांग्रेस ने सालों तक इसे लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1990 में जब लाया गया, तब राजीव गांधी ने 2 घंटे 43 मिनट तक भाषण करके ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम मोदी के नेतृत्व में किया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण देने का काम पहली बार हमारे नेता नरेन्द्र मोदी ने किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय हरियाणा को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस की सरकारें बनती थी, तो एक सरकार के आने पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचती था, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंचती थी। एक सरकार एक जिले का विकास करती थी और दूसरी सरकार दूसरे क्षेत्र का विकास करती थी। जबकि भाजपा ने संपूर्ण हरियाणा का विकास करने वाली सरकार देने का काम किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने का काम किया है। अगर ये यहां भी आ गए तो यहां पर भी यही करेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हरियाणा में किसी भी हालत में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे।

डोडा मुठभेड़ के बाद राहुल का सरकार पर निशाना

नईदिल्ली। जम्मू-कश्मीर के डोडा में ड्यूटी के दौरान चार सैनिकों की मौत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि भारत के सैनिक और उनके परिवार भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक एक्स पोस्ट किया है। अपने पेस्ट में राहुल ने लिखा कि आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थयात्रा: एकनाथ

मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुजुर्गों को देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की मुफ्त तीर्थयात्रा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लागू करने की घोषणा हाल ही में की है। तद्नुसार, सरकार ने रविवार को इस योजना का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी धर्मों के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए देश के महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों की मुफ्त तीर्थयात्रा के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लागू करने की घोषणा की है. इस योजना में भारत में कुल 73 और महाराष्ट्र राज्य में 66 तीर्थस्थलों को शामिल किया गया है। देश और राज्य के लगभग सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य के सभी धर्मों के वरिष्ठ नागरिकों को भारत के तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा करने का अवसर मिलेगा ताकि वे मन की शांति प्राप्त कर सकें और देश में प्रमुख तीर्थयात्राओं पर जाकर आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकें। इस योजना के तहत राज्य और देश के प्रमुख तीर्थस्थलों को कवर किया जाएगा और इस योजना के तहत निर्दिष्ट तीर्थ स्थलों में से किसी एक की तीर्थयात्रा के लिए पात्र व्यक्ति को इस योजना का एकमुश्त लाभ मिलेगा, जिसमें यात्रा खर्च के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम 30,000 रुपये की सीमा होगी। इसमें आवास, भोजन और परिवहन शामिल हैं। लाभार्थी की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार होनी चाहिए। लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य का निवासी और 60 वर्ष से अधिक आयु का वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए। चार धाम यात्रा, माता वैष्णवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा देश के अन्य धर्मों की प्रमुख तीर्थयात्राओं में से हैं। जहाँ अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों का जीवन में एक बार जाने का सपना होता है।

प्रधानमंत्री 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को कर सकते हैं संबोधित

न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हाल ही में रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी हाई-प्रोफाइल द्विपक्षीय यात्राएं पूरी की हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की अनंतिम सूची के अनुसार 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की आम बहस 24 से 30 सितंबर तक होगी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा सोमवार को जारी आम बहस के लिए वक्ताओं की अनंतिम सूची के अनुसार, भारत के सरकार प्रमुख 26 सितंबर की दोपहर में उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सूची अंतिम नहीं है और संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सत्र से पहले के हफ्तों में वक्ताओं की अद्यतन अनंतिम सूची जारी करता है ताकि नेताओं, मंत्रियों और राजदूतों की उपस्थिति, कार्यक्रम और बोलने के स्लॉट में किसी भी संशोधन को दर्शाया जा सके।

परंपरागत रूप से बहस में पहला वक्ता ब्राजील 24 सितंबर को उच्च स्तरीय सत्र की शुरुआत करेगा, उसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति जो बिडेन नवंबर में अपने देश में राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मंच से वैश्विक नेताओं को अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम संबोधन देंगे।

प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने पिछले महीने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल

के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, ने पिछली बार सितंबर 2021 में वार्षिक उच्च स्तरीय यूएनजीए सत्र को संबोधित किया था। उन्होंने पिछले साल 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का दौरा किया था, जो बिडेन द्वारा आयोजित एक राजकीय यात्रा के लिए वाशिंगटन डीसी जाने से पहले विश्व निकाय के मुख्यालय के उत्तरी लॉन में ऐतिहासिक योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया था।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आम बहस की शुरुआत से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, उसके बाद महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष द्वारा संबोधन होगा। गुटेरेस उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भविष्य के महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 20-21 सितंबर को कार्रवाई के दिन और 22-23 सितंबर को शिखर सम्मेलन निर्धारित है।

विश्व के नेता भविष्य के लिए समझौते को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एकत्रित होंगे, जिसमें एक वैश्विक डिजिटल समझौता और भविष्य की पीढ़ियों पर घोषणा शामिल होगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, शिखर सम्मेलन एक उच्च स्तरीय आयोजन है, जो विश्व नेताओं को एक साथ लाकर इस बात पर नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए प्रेरित करता है कि हम कैसे एक बेहतर वर्तमान प्रदान करें और भविष्य की सुरक्षा करें।

इसमें कहा गया है, प्रभावी वैश्विक सहयोग हमारे अस्तित्व के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन अविश्वास के माहौल में इसे हासिल करना मुश्किल है, पुरानी संरचनाओं का उपयोग करना जो अब आज की राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

हार्दिक पांड्या ही बनेंगे टी20 कप्तान?

नई दिल्ली। भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ इस महीने के अंत में सीमित ओवरों की सीरीज खेलनी है। इसके लिए कभी भी टीम को घोषणा हो सकती है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा के बाद टी20 प्रारूप का कप्तान माना जा रहा है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है। अब खबर आ रही है कि श्रीलंका के खिलाफ 27 जुलाई से होने वाली सीरीज में हार्दिक ही टीम की कमान संभालेंगे।

हार्दिक हाल ही में संपन्न हुए टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के उपकप्तान की भूमिका निभा रहे थे। रोहित ने इस टूर्नामेंट के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी जिसके बाद इसकी चर्चा तेज हो गई थी कि इस प्रारूप में भारत का अगला कप्तान कौन होगा? बीसीसीआई के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा. रोहित के नेतृत्व में हार्दिक टी20 के उपकप्तान थे। वह पूरी तरह फिट हैं और तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए उपलब्ध हैं तथा हार्दिक टीम का नेतृत्व करेंगे।

सूत्रों की मानें तो हार्दिक कप्तान होंगे, लेकिन उपकप्तान कौन होगा इसे लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। इसे लेकर शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव के नाम पर चर्चा चल रही है। शुभमन ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम की कमान संभाली थी जहां भारत 4-1 से जीतने में सफल रहा था। दूसरी तरफ, सूर्यकुमार ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में कप्तानी की थी। वनडे सीरीज को लेकर सूत्रों ने बताया कि हार्दिक ने छुट्टी की मांद की है और इस बारे में नियमित कप्तान रोहित शर्मा को बता दिया गया है। अधिकारी ने कहा, वनडे से ब्रेक लेना निजी कारणों के चलते है। मीडिया में जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि हार्दिक को फिटनेस की समस्या है, यह पूरी तरह गलत है। वनडे में केएल राहुल और शुभमन गिल में से किसी को कप्तान बनाया जा सकता है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए सेंसेक्स, निफ्टी

नईदिल्ली। स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 52 अंक चढ़कर अबतक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी नए शिखर 24,600 के ऊपर पहुंच गया। दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों, दूरसंचार और चुनिंदा आईटी शेयरों में लिवाली तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह से बाजार में तेजी बनी रही। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 51.69 अंक यानी 0.06 प्रतिशत चढ़कर अपने अबतक के उच्चतम स्तर 80,716.55 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 233.44 अंक यानी 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 80,898.30 अंक तक गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 26.30 अंक यानी 0.11 प्रतिशत की तेजी के साथ नये शिखर 24,613 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 74.55 अंक यानी 0.30 प्रतिशत चढ़कर रिकॉर्ड 24,661.25 अंक तक चला गया था।

वेदांता का क्यूआईपी हुआ लॉन्च

नईदिल्ली। दिग्गज माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड ने अपना योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) लॉन्च किया। कंपनी ने इसकी जानकारी एक एक्सचेंज फाइलिंग में दी। इसके फंडराइजिंग समिति ने रू. 461.26 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है। क्यूआईपी के माध्यम से कंपनी रू. 6,000 करोड़ जुटाना चाहती है। वहीं ओवर-सब्सक्रिप्शन की स्थिति में अतिरिक्त रू. 2,000 करोड़ जुटाने का विकल्प है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और व्हाइटओक उन संस्थानों में शामिल हैं जिन्होंने इसमें बोली लगाई है। कंपनी क्यूआईपी से जुटाए गए रुपयों का इस्तेमाल अपने कर्ज कम करने और कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। बता दें कि इस साल मई की शुरुआत में कंपनी ने कर्ज कम करने के लिए 8,500 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना की घोषणा की थी।

स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे 346 रक्षा उत्पाद

नई दिल्ली। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा उत्पादों को आयात को कम करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग ने 346 वस्तुओं की पांचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) जारी की है। इस सूची में रणनीतिक रूप से अहम लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सिस्टम, सब-सिस्टम, असेंबली, सब-असेंबली और रक्षा उत्पादों के लिए कच्चा माल शामिल है। इसके बाद सरकारी रक्षा कंपनियां इन उत्पादों का आयात नहीं कर सकेंगी। रक्षा मंत्रालय ने साल 2020 में सृजन डिफेंस पोर्टल (https://srijandefence.gov.in) लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर रक्षा उत्पादन विभाग और सेवा मुख्यालय, एमएसएमई कंपनियों और विभिन्न स्टार्ट-अप सहित उद्योगों को स्वदेशीकरण के लिए रक्षा वस्तुएं प्रदान करते हैं। स्वदेशीकरण की जो नई सूची तैयार की गई है, उनकी एक समयसीमा के बाद भारतीय उद्योगों से खरीद की जाएंगी।

स्मार्टवर्ल्ड डेवलपर्स ने दिया 581 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट

नई दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी स्मार्टवर्ल्ड डेवलपर्स ने गुरुग्राम में अपनी लक्जरी आवासीय परियोजना के निर्माण के लिए अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को 581 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा, परियोजना 'स्मार्टवर्ल्ड द एडिशन' गुरुग्राम के सेक्टर 66 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर स्थित है। इसके साथ कंपनी लक्जरी आवासीय खंड में प्रवेश कर रही है। इस परियोजना से '' 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल होने की उम्मीद है।'' गुरुग्राम स्थित स्मार्टवर्ल्ड डेवलपर्स की स्थापना 2021 में की गई थी। बयान के अनुसार, 30 लाख वर्ग फुट के बिक्री योग्य क्षेत्र और 10 एकड़ में फैली इस परियोजना में करीब 900 अपार्टमेंट होंगे। कंपनी गुरुग्राम में कई परियोजनाओं को अंजाम दे रही है।

बजट से मध्यवर्ग की अपेक्षाएं, टैक्स छूट से बढ़ेगी खरीदारी-खपत

मधुरेंद्र सिन्हा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर बजट पेश करने की तैयारी में हैं। लोकसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने जो अंतरिम बजट पेश किया था, वह भले ही संतुलित बजट था, लेकिन उसमें मध्यवर्ग को कोई राहत नहीं दी गई थी। अब जब वह पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं, तो लोगों, खासकर मध्यवर्ग की उनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि फिलहाल वह राहत देने की स्थिति में हैं।

यह मध्यवर्ग ही है, जो बड़े पैमाने पर खरीदारी करके अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनाए रखने में मदद करता है। वित्तमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि देश में बढ़ती खपत के कारण ही जीडीपी में तेजी दिख रही है। उन्होंने माना कि खपत बढ़ने से कारखानों की भी रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे रोजगार बढ़ता है, जो अंततः लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाकर खपत को बढ़ावा देता है। आज भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग भी इसी वर्ग के बूते फल-फूल रहा है। यही नहीं, देश का उच्च मध्यवर्ग लग्जरी आइटमों की खरीदारी करके भारी टैक्स भी दे रहा है। वह अच्छी शिक्षा पाने के लिए अपने बच्चों को?विदेशी कॉलेज-यूनिवर्सिटी में भेजता है और भारतीय बैंकों को मोटा ब्याज देकर मालामाल करता है। मध्यवर्ग का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान उल्लेखनीय है, इसलिए वह सरकार से कुछ प्रोत्साहन की उम्मीद रखता है।

इस बार सरकार की उम्मीदों से कहीं ज्यादा टैक्स की वसूली हुई है। प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी वसूली बढ़कर हर महीने औसतन पौने दो लाख करोड़ रुपये तक जा पहुंची है। दूसरी ओर आयकर में वसूली भी बढ़ गई है। यानी सरकार के पास राहत देने के लिए काफी गुंजाइश है।

वित्तमंत्री चाहें, तो आयकर दरों में कटौती कर सकती हैं, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही है। मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग के समक्ष आयकर एक बड़ी बाधा है, जो उसकी खर्च करने की क्षमता को सीमित कर रहा है। देश में महंगाई बढ़ने से लोगों को घर चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। जनता की मांग है कि पुरानी आयकर दर को घटाकर 5 से 20 फीसदी कर दिया जाए, क्योंकि आयकर देने वाला जीएसटी भी दे रहा है। कुछ मामलों में तो करदाता कुल मिलाकर 50 फीसदी टैक्स दे रहा है। फिर भी उसे अपने बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा या मुफ्त स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही है। टैक्स में कटौती करने से उनकी खपत करने की ताकत भी बढ़ेगी। कुछ कारोबारियों का सुझाव है कि सभी प्रकार के टैक्स हटाकर एक देश-एक टैक्स की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी बैंक लेन-देन कर प्रणाली लागू करनी चाहिए, ताकि कर अनुपालन में लगने वाले समय को बचाकर उसे कारोबार में लगाया जा सके। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तमंत्री 80सी की सीमा बढ़ाएं। वर्ष 2014 में तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इसे बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दिया था, जिससे करदाताओं को फायदा हुआ था। पिछले दस साल में महंगाई इतनी बढ़ गई कि अब इसका भी ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए 80सी की सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपये कर देना चाहिए। गौरतलब है कि 80 सी में लगाया गया धन सरकार के भी काम आता है।

सरकार को 80 डी की सीमा में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। यह मेडिकल खर्च से जुड़ा हुआ है, जिसकी सीमा लंबे समय से नहीं बढ़ी है, जबकि चिकित्सा लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही चिकित्सा बीमा पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को भी कम करना चाहिए, क्योंकि बीमा कंपनियों ने अपने प्रीमियम अनाप-शनाप तरीके से बढ़ा दिए हैं। इस वजह से लाखों लोग बीच में ही स्वास्थ्य बीमा छोड़ देते हैं। बीमा को लोकप्रिय बनाने के लिए जरूरी है कि उसकी प्रीमियम पर टैक्स घटे। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होगा। अभी सरकार का खजाना भरा हुआ है और आने वाले समय में इसमें कुछ और बढ़ोतरी होगी। इसलिए वित्तमंत्री लोगों की मांगें पूरी कर सकती हैं। इतिहास गवाह है कि टैक्स दर घटाने से टैक्स वसूली नहीं घटती। जीडीपी बढ़ाने के लिए यह जरूरी है, क्योंकि मध्यवर्ग को दी गई टैक्स छूट, खरीदारी की शक्ल में बाजारों में आएगी और फिर खपत बढ़ेगी, जो जीडीपी में तेजी का कारण बनेगी।

अमृतकालः छत्तीसगढ़ विजन @2047 तैयार करने युवा, कृषक, महिला एवं प्रबुद्धजनों से किया गया संवाद

हमारा संकल्प 2047 तक बनाएंगे विकसित छत्तीसगढ़ः साय

01 नवम्बर को राज्य की नई औद्योगिक नीति-2024-29 होगी जारी-राज्य स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ विजन 2047 जनता को किया जाएगा समर्पित

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट सभी की भागीदारी से तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है इसे पूरा करने के लिए हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री आज यहां न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार करने के लिए राज्य नीति आयोग द्वारा आयोजित मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के युवाओं, कृषकों, महिलाओं और प्रबुद्धजनों ने अपने-अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने अगले पांच साल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने में छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य है जहां प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, वन संपदा और मानव संसाधन हैं। यहां की धरती उर्वरा है, मेहनतकश किसान हैं। यहां के संसाधनों का वैल्यू एडिशन करके हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकते हैं। इसमें सभी का सहयोग आवश्यक होगा। छत्तीसगढ़ युवा प्रदेश है, हमने नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें वोकेशन ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में सबके सहयोग से रिफॉर्म ला रही है। सरकार काम-काज में भी पारदर्शिता लाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सरकार की नीति करप्शन के प्रति जीरो टालरेंस की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं, कृषकों, महिलाओं और प्रबुद्धजनों ने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण विचार साझा किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट और नई उद्योग नीति राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2024 को आम जनता को समर्पित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में जैविक कृषि को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। युवाओं ने भी आगामी भविष्य को लेकर अपना बेहतर दृष्टिकोण रखा है। कार्यक्रम में नारी शक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, यहां आने के लिए उनका विशेष धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं स्वयं किसान का बेटा हूं मेरी भी कृषि में बहुत रूचि है मैं जब भी गांव जाता हूं तो अपने खेत में जरूर समय बिताता हूं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के युवा, कृषक, महिला और प्रबुद्धजनों के साथ विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर परिचर्चा में मुख्यमंत्री श्री साय ने ड्रोन दीदी को लेकर आए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भिलाई में तकनीकी विश्वविद्यालय में ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का आह्वान किया है, जिसमें ड्रोन दीदी का भी अहम योगदान होगा। मुख्यमंत्री ने पद्मश्री जागेश्वर यादव की तारीफ़ करते हुए कहा कि जागेश्वर जी पढ़े-लिखे नहीं हैं, उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता, हाफ पेंट पहनकर और बिना चप्पल के अपना काम चलाते हैं लेकिन आज इन्होंने कोरवा-बिरहोर समुदाय की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, मैं उनका अभिनन्दन करता हूं।

वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि कार्यक्रम में प्राप्त सुझावों का नीति आयोग द्वारा संकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन तथा सर्विस सेक्टर में भी असीम संभावनाएं हैं। वर्तमान में कृषि में रसायनिक खाद के उपयोग से कैंसर रोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा। कृषि में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव फॉर्मिंग के लिए किसानों की जमीन को एक साथ करने के लिए विचार करने की जरूरत है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए जमीन की लेबलिंग, फेंसिंग और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता आदि पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में स्किल डेव्हलपमेंट को भी बढ़ाना होगा। मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष राज्य नीति आयोग श्री अमिताभ जैन और योजना विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। संवाद कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम में काष्ठ शिल्पकार एवं पद्मश्री से सम्मानित अजय मण्डावी एवं पद्मश्री जागेश्वर यादव, कोण्डागांव से आयी महिला कृषक उदेश्वरी, शुभम दीक्षित, सिमरन, अंकित जैन, शताब्दी पाण्डेय, सुधा वर्मा सहित अनेक लोगों ने सुझाव दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सलाहकार धीरेन्द्र तिवारी, राज्य नीति आयोग के सदस्य के. सुब्रमण्यम, सचिव अनूप श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत भी उपस्थित थे।

सीजीपीएससी मामलाः दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाईः मुख्यमंत्री, हम भी जांच के पक्षधरः कांग्रेस

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग भर्ती में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है. सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है. तो वहीं सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम किसी तरीके की जांच से डर नहीं रहे हैं. हम भी जांच के पक्षधर है. हम किसी प्रकार की जांच से डरते नहीं है. एक कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने सीजीपीएससी की सीबीआई जांच को लेकर कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था. भाजपा की सरकार बनेगी तो यहां के युवाओं के साथ पीएससी में जो घोटाले हुए हैं. इसकी सीबीआई जांच होगी. दोषियों के ऊपर कार्यवाही होगी. सीबीआई अपनी जांच प्रारंभ कर चुकी है. बहुत शीघ्र दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी. मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र का यह एक प्रमुख हिस्सा था. सरकार बनते ही इसकी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी थी. अब सीबीआई ने जांच प्रारंभ की है. छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ कांग्रेस सरकार में जो अन्याय और धोखा हुआ है. इससे छुटकारा और न्याय मिलेगा. वही छत्तीसगढ के विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ था. युवाओं को इस बात को लेकर

में पीड़ा थी. सीजीपीएससी में जो अनियमितता हुई है. उसकी जांच हो रही है, जो भी दोषी है उन पर निश्चित ही कार्रवाई होगी. पीएससी घोटाले जांच पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस राज के दौरान पीएससी में माफिया राज चला है. हमारी सरकार की प्राथमिकता है. भर्तियों में गड़बड़ियां समाप्त हो. हमने सीबीआई जांच का वादा किया है. जांच की जा रही है. कांग्रेस सरकार की तुलना में आने वाले पांच सालों में कई गुना ज्यादा भर्तियां होगी.विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि आज परीक्षा देने वाली संस्थाओं और परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ है. पीएम मोदी की गारंटी थी, जांच शुरू हुई है. योग्य प्रतियोगी को अवसर मिलेगा. कांग्रेस का मापदंड नीट के मामले में अलग हैं और सीजीपीएससमामले पर अलग है. पीएम मोदी की गारंटी थी, हम जांच कराएंगे. जांच शुरू हो गई, छग के बेरोजगारों को न्याय मिलेगा. सीजीपीएससमामले पर सीबीआई की जांच को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा की जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. इसके बाद सब संतुष्ट हो जाएंगे. मामले में पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए. कोई दिक्कत नहीं है. सही तरीके से जांच होनी चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आएगी.

साय सहित मंत्रियों का दिल्ली दौरा, राजनीतिक हलचल तेज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कल यानी बुधवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे. सीएम सुबह करीब 9 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे. वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा रात की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेंगे, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी की भी इस दौरे पर जाने की खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सदन में रात्रि विश्राम करेंगे. मुख्यमंत्री के इस दौरे में जाने की खबर के बाद छत्तीसगढ़ में रजनीतिक हलचल तेज हो गई है. माना जा रहा है कि रात में ही सीएम साय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर मंत्रिमंडल के विस्तार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं. बता दें कि राज्य कैबिनेट में मंत्री के 2 पद खाली हैं. एक पद पहले से खाली रखा गया था, जबकि दूसरा पद वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे की वजह से खाली हुआ है. राज्य कैबिनेट में 2 नए मंत्रियों की एंट्री होनी है. ऐसे में सीनियर नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम साय योग्य दावेदारों के नाम पर भी मंथन कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़/राजधानी — प्रमुख समाचार

समीर कान्त माथुर बने एसईसीआर के नए सीपीआरओ

रायपुर. समीर कान्त माथुर अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी होंगे. उन्होंने आज पदभार संभाल लिया. विकास कुमार कश्यप की पदस्थापना परिचालन विभाग, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में की गई है. समीर कान्त माथुर भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएसई) के 2011 बैच के अधिकारी है. माथुर वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उप महाप्रबंधक (सा.) के पद पर पदस्थ हैं एवं वे उप महाप्रबंधक (सा.) के साथ मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी का कार्यभार भी देखेंगे.

18 जुलाई को होने वाला जनदर्शन स्थगित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 18 जुलाई को अपरिहार्य कारणों से नहीं होगा।

पहाड़ी कोरवाओं को मिला रोजगार तो समाज के बच्चे पहुँचने लगे शिक्षा के द्वार

रायपुर। विशेष पिछड़ी जनजाति के पहाड़ी कोरवा गुरवार सिंह, बिरसराम, करम सिंह कोरबा जिले के वनांचल के सारबाहर,छातीबहार के रहने वाले हैं। आज इन्हें मलाल है कि उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। किसी ने पांचवीं तक तो किसी ने आठवी से पहले ही स्कूल और पढ़ाई से नाता तोड़ लिया था। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले इन पहाड़ी कोरवाओं का कहना है कि काश उन्होंने उस वक्त पढ़ लिया होता। बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो आज उन्हें जंगल में बकरी चराना नहीं पड़ता। वे भी किसी स्कूल और अस्पताल में नौकरी कर रहे होते और उन्हें गरीबी से नहीं जूझना पड़ता। हालांकि उनका कहना है कि घर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं था, इसलिए वे स्कूल नहीं जा सके। अब जबकि पहाड़ी कोरवाओं को नौकरी मिलने लगी हैं तो उन्हें भी लगने लगा है कि पढ़ाई का बहुत महत्व है.

बीजापुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है: कश्यप

रायपुर। वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप अपने एक दिवसीय बीजापुर जिले के प्रवास के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने अपने उद्बोधन में जिला प्रशासन की टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि बीजापुर जिला अब शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छूने लगा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच अब सुनिश्चित हो रही है। मंत्री कश्यप ने कहा कि बीजापुर के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। बस उन्हें सही अवसर मिलना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकार की योजना से समूचे बस्तर के आदिवासी बच्चों का भविष्य बेहतर हो रहा है। बीजापुर का नवोदय विद्यालय राज्य में दूसरे स्थान पर है यह जिले के लिए गर्व की बात है। यहां केन्द्रीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय सहित ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी में उच्च स्तर के शैक्षणिक संस्थान है जिससे जिले के बच्चों का बेहतर भविष्य तय हो रहा है। मंत्री कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा में व्यापक बदलाव आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए है। स्कूलों की अद्योसंरचना, शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण, गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति सहित तमाम योजनाएं बेहतर शिक्षा के लिए कारगर सिद्ध हो रही है।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा राज्य स्तरीय आनलाईन प्रशिक्षण उन्मुखीकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

रायपुर. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल की द्वितीय मुख्य परीक्षा 23 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक आयोजित होगी। परीक्षा के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर आनलाईन प्रशिक्षण उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया । माध्यमिक शिक्षा मण्डल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी पिल्ले एवं सचिव श्रीमती पुष्पा साहू के मार्गदर्शन में 15 एवं 16 जुलाई को उक्त प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जिसमें राज्य के सभी 227 परीक्षा केन्द्रों से केन्द्राध्यक्ष शामिल हुए। उन्मुखीकरण में मुख्य रूप से परीक्षा पूर्व तैयारी, परीक्षा के दिन की कार्यवाही परीक्षा समाप्ति पश्चात की कार्यवाही किस प्रकार से किया जाना है इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। परीक्षा केन्द्र में विभिन्न मुख्य व्यवस्था बिजली, पेयजल तथा प्रसाधन की उचित व्यवस्था, मुख्य द्वार पर बैठक व्यवस्था की जानकारी का नोटिस बोर्ड, प्रतिदिन छात्र संख्या अनुसार पुलिस व्यवस्था, सूचना पटल पर आवश्यक सूचना, समय-सारणी लगाना, उत्तर पुस्तिका के बंडल तैयार करने हेतु आवश्यक सामग्री की समुचित मात्रा, स्थायी केन्द्र निरीक्षण पंजी का संधारण, 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाले परीक्षार्थियों को लेखक की नियमानुसार पात्र परीक्षार्थियों हेतु बैठक व्यवस्था, छात्र संख्या एवं कक्ष क्षमता अनुसार परीक्षा कक्ष का चयन, प्रकाशयुक्त एवं हवादार कक्ष, आवश्यक एवं पर्याप्त फर्नीचर का प्रबंध परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका में लालस्याही या पेंसिल का उपयोग न किए जाने हेतु सूचित करना.

विद्युत दर की बढ़ोत्तरी को लेकर स्टील एसोसिएशन ने की सीएम साय से मुलाकात

रायपुर। बिजली की बढ़ी हुई दर को लेकर सीएम विष्णु देव साय से छग फेरो एलाय प्रोडूसर एसोसिएशन, छग मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन और व्यापारी एकता पैनल के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सीएम साय को बताया की विद्युत मंडल के अव्यवहारिक विद्युत दर की वृद्धि से उद्योग बंद होने के कगार पर है. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पूर्व में छग विद्युत की दरें अन्य राज्य के मुकाबले कम थी. लेकिन पिछले दिनों की गई वृद्धि से छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य ओ?डिसा, बंगाल, झारखंड, मध्यप्रदेश से अधिक दर हो गई है. जबकि छत्तीसगढ़ के उत्पादन का 70-75 प्रतिशत बिजली अन्य राज्यों में खपत होती है. हमारी विद्युत दरें बढ़ने से अन्य राज्यों में जाने वाले माल जाना बंद हो जाएगा. क्योंकि हमारे उत्पादन का रॉ मटेरियल विद्युत ही है. अगर यह वृद्धि वापस न ली गई तो यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार से भी वंचित होना पड़ेगा.

धान खरीदी केन्द्र में 1.53 करोड़ का घपला, खरीदी प्रभारी एवं ऑपरेटर के विरूद्ध एफआईआर के निर्देश

बिलासपुर/रायपुर। मस्तुरी ब्लॉक के धान खरीदी केन्द्र गोडाडीह में धान खरीदी केन्द्र में गड़बड़ी पाये जाने पर खरीदी प्रभारी प्रकाश लहरे एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर योगेश कुमार लहरे के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर उप आयुक्त सहकारिता श्रीमती मंजू पाण्डेय ने लोहर्सी सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक को संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराकर सूचित करने को कहा है। गौरतलब है कि संयुक्त जांच टीम द्वारा कराये गये जांच में 4950.21 क्विंटल धान का घपला किया जाना प्रमाणित हुआ है जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 53 लाख 46 हजार है।

उल्लेखनीय है कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोडाडीह पंजीयन क्रमांक 575 की जांच सहायक खाद्य अधिकारी मस्तुरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी, खाद्य निरीक्षक मस्तुरी एवं बैंक प्रबंधक लोहर्सी द्वारा 16 जून 2024 को संयुक्त रूप से किया गया। जांच टीम के प्रतिवेदन के अनुसार उस समय खरीदी प्रभारी के रूप में प्रकाश लहरे एवं ऑपरेटर के रूप में योगेश कुमार लहरे पदस्थ हैं, जो जांच के दौरान मौके पर उपस्थित थे।

रिपोर्ट के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में खरीदी केन्द्र द्वारा 62560.40 क्विंटल धान का खरीदी किया जाना पाया गया। जिसमें से 56604.70 क्विंटल धान का परिदान होना एवं 5955.70 क्विंटल धान का शेष होना पाया गया। मौके पर खरीदी केन्द्र में उपलब्ध धान का सत्यापन किया गया। पांच विभिन्न स्टेकों में 3087 बोरी धान भौतिक रूप से पाया गया। इसमें से 10 बोरे का रेण्डमली वजन किया गया। औसत वजन 32.57 किलोग्राम पाया गया। इस प्रकार 3087 बोरी धान का कुल वजन 1005.49 क्विंटल धान भौतिक रूप से उपलब्ध पाया गया।

धान का ऑनलाईन शेष स्टॉक 5955.70 क्विंटल से भौतिक रूप से प्राप्त धान 1005.49 क्विंटल से घटाने पर 4950.21 क्विंटल धान कम होना पाया गया। कलेक्टर के खाद्य शाखा द्वारा 10 जुलाई को कराये गये जांच में भी इतनी ही धान की मात्रा कम पायी गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार गोडाडीह के धान खरीदी प्रभारी प्रकाश लहरे एवं ऑपरेटर योगेश कुमार लहरे द्वारा प्रथम दृष्टया धान का व्यपवर्तन किया जाना एवं खरीदी में लापरवाही किया जाना पाया गया।

जो कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जारी धान खरीदी नीति की कण्डिका 16.9 का खुला उल्लंघन है। इसलिए बैंक के शाखा प्रबंधक को उक्त दोनो कर्मचारियों के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.